Pew Research Center

प्रकाशन के लिए महीना, दिनांक, वर्ष

भारत की धार्मिक संरचना

भारत में सभी धार्मिक समूह प्रजनन दरों में बड़ी गिरावटें दर्शाते हैं, जो कि समय के साथ देश की धार्मिक संरचना में परिवर्तन को सीमित करती हैं

स्टेफैनी क्रैमर द्वारा लिखित

मिडिया और अन्य पूछताछ के लिए:

स्टेफैनी क्रैमर, वरिष्ठ शोधकर्ता
ऐना शिलर, वरिष्ठ संचार प्रबंधक

202.419.4372

www.pewresearch.org

अनुशंसित उद्धरण
PEW रिसर्च सेंटर, TK, 2021, "भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर के बारे में**

PEW रिसर्च सेंटर एक ऐसा अपक्षपाती तथ्य समूह है जो अमरीका और दुनिया को आकार देने वाले मुद्दों, दृष्टिकोणों और रुझानों के बारे में जनता को सूचित करता है। यह नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त नहीं करता है। सेंटर जनमत मतदान, जनसांख्यिकीय अनुसंधान, विषय वस्तु विश्लेषण और डेटा-आधारित अन्य सामाजिक विज्ञान अनुसंधान आयोजित करता है। यह अमरीकी राजनीति और नीति; पत्रकारिता और मीडिया; इंटरनेट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी; धर्म और सार्वजनिक जीवन; हिस्पैनिक रुझानों; वैश्विक दृष्टिकोणों और रुझानों; और अमरीकी सामाजिक और जनसांख्यिकीय रुझानों का अध्ययन करता है। www.pewresearch.org सेंटर की सभी रिपोर्ट्स www.pewresearch.org पर उपलब्ध हैं। PEW रिसर्च सेंटर, PEW चैरिटेबल ट्रस्ट्स की एक सहायक कंपनी है, जो इसका प्राथमिक वित्त पोषक है।

ग्लोबल रिलिजियस फ्यूचर्स प्रोजेक्ट के लिए वित्तपोषण PEW चैरिटेबल ट्रस्ट्स और जॉन टेम्प्लेटन फाउंडेशन से आता है। 3© Pew रिसर्च सेंटर 2021

यह हमने कैसे किया

PEW रिसर्च सेंटर का यह अध्ययन भारत की धार्मिक संरचना औऱ 1951 और 2011 के बीच यह किस तरह से बदला इस बात का वर्णन करने, तथा परिवर्तन के कारणों की जाँच करने के लिए किया गया था। यह भारत के तीन सबसे बड़े धार्मिक समूहों - हिंदू, मुस्लिम और ईसाई - पर केंद्रित है और जहाँ उपयुक्त डेटा उपलब्ध हुआ है, वहाँ इसमें बौद्ध, सिख और जैन भी शामिल किए गए हैं।

समय के साथ जनसंख्या के आकारों की जानकारी भारत की दशवार्षिक जनगणना से आई है। जनगणना ने 1881 से भारत के निवासियों के बारे में उनके धर्म सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की है। प्रजनन क्षमता और इसका शिक्षा और महिला के निवास स्थान जैसे कारकों से संबंध के बारे में डेटा भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NHFS) से प्राप्त किए गए हैं। NHFS प्रजनन के बारेमें अधिक विस्तृत जानकारी वाला एक बड़ा, राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधिक पारिवारिक सर्वेक्षण है।

प्रवासन पर डेटा मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग से प्राप्त किया गया है। धार्मिक परिवर्तन (या धर्मांतरण) और अंतर्धार्मिक विवाहों पर सर्वेक्षण प्रतिक्रियाPEW रिसर्च सेंटर द्वारा 2019-2020 में आयोजित 29,999 भारतीय वयस्कों के सर्वेक्षण से प्राप्त हैं।

19 अगस्त, 2021 की दिनांक तक, भारतीय इतिहास, कानूनों, सीमा परिवर्तनों और सर्वेक्षण विलंब के संदर्भ सटीक हैं।

अधिक जानकारी के लिए, इस रिपोर्ट की कार्य-विधि देखें।

अभिस्वीकृतियाँ

यह रिपोर्ट PEW रिसर्च सेंटर द्वारा PEW-टेम्प्लेटन ग्लोबल रिलिजियस फ्यूचर्स प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में तैयार की गई थी, जिसमें धार्मिक बदलाव और दुनिया भर के समाजों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। ग्लोबल रिलिजियस फ्यूचर्स प्रोजेक्ट के लिए वित्तपोषण PEW चैरिटेबल ट्रस्ट्स और जॉन टेम्प्लेटन फाउंडेशन से आता है।

यह रिपोर्ट निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और विश्लेषण पर आधारित एक सहयोगात्मक प्रयास है। pewresearch.org/religion पर संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त करें।

प्राथमिक शोधकर्ता

स्टेफैनी क्रैमर, *वरिष्ठ शोधकर्ता*

अनुसंधान दल

युनपिंग टोंग, *रिसर्च एसोसिएट (अनुसंधान सहयोगी)*
कॉनराड हैकेट, *अनुसंधान के एसोसिएट निदेशक और वरिष्ठ जनसांख्यिकी विशेषज्ञ*
एनी फ़ेंग्यान शी, *वरिष्ठ शोधकर्ता*
जैकब ओसुबल, *अनुसंधान सहायक*
आलन कूपरमैन, *धर्म अनुसंधान निदेशक*

संपादकीय और ग्राफिक डिजाइन

डालिया फ़ाहमी, *वरिष्ठ लेखक/संपादक*
माइकल लिपका, *संपादकीय प्रबंधक*
डेविड केंट, *वरिष्ठ कॉपी एडिटर*
रेबेका लेपर्ट, *संपादकीय सहायक*
बिल वेबस्टर, *वरिष्ठ इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स डिजाइनर*

संचार और वेब प्रकाशन

स्टेसी रोसेनबर्ग, *एसोसिएट निदेशक, डिजिटल*
ट्रैविस मिचेल, *डिजिटल निर्माता*
शाजिया आबिदी, *एसोसिएट वेब डेवलपर*
ऐना शिलर, *वरिष्ठ संचार प्रबंधक*
केल्सी बेवरिज, *संचार सहयोगी*

PEW रिसर्च सेंटर के अन्य लोग जिन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया, उनमें नेहा सहगल, अनुसंधान की एसोसिएट निदेशक, और जोनाथन इवांस, रिसर्च एसोसिएट शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्व रिसर्च एसोसिएट जोई मार्शल और पूर्व प्रशिक्षु ओमकार जोशी का इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इस रिपोर्ट पर सेंटर को भी कई प्रख्यात विद्वानों की रिपोर्ट से भी बहुमूल्य सलाह मिली जिनमें शामिल हैं: मोनिका दास गुप्ता, मैरीलैंड विश्वविद्यालय और मैरीलैंड जनसंख्या अनुसंधान केंद्र में समाजशास्त्र की अनुसंधान प्रोफेसर; श्रिया अय्यर, अर्थशास्त्र में यूनिवर्सिटी रीडर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंट कैथरीन कॉलेज की फ़ेलो; देवेश कपूर, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में दक्षिण एशियाई अध्ययन के स्टार फाउंडेशन प्रोफेसर;

जबकि इस रिपोर्ट का विश्लेषण इन सलाहकारों के साथ हुए हमारे परामर्श के मार्गदर्शन में हुआ, तब भी केवल PEW रिसर्च सेंटर ही डेटा की व्याख्या और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

विषय-सूची

PEW **रिसर्च सेंटर के बारे में** 1
यह हमने कैसे किया 2
अभिस्वीकृतियाँ 3
विषय-सूची 5
1. **जनसंख्या वृद्धि और धार्मिक *संरचना*** 12
बँटवारे के बाद से भारत की धार्मिक संरचना काफी हद तक स्थिर है। 17
2050 तक आगे देखते हुए 21
2. **धार्मिक परिवर्तन के कारण** 22
परिवर्तन के कारण: प्रजनन 23
परिवर्तन के कारण: प्रवासन 29
परिवर्तन के कारण: धार्मिक परिवर्तन 32
3. भारतीय राज्यों और प्रदेशों की धार्मिक जनसांख्यिकी 33
राज्य स्तर पर, हाल के जनगणना दशक में धार्मिक विभाजन अपेक्षाकृत स्थिर थे। 37
कार्य-विधि 44
स्रोत 44
डेटा की सीमाएँ 45
मानचित्र सीमाएं और अनुपलब्ध डेटा 45
मॉडलिंग पर विस्तृत जानकारी 46

भारत की धार्मिक संरचना

भारत में सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जो कि समय के साथ देश की धार्मिक संरचना में परिवर्तन को सीमित करती है

हाल के दशकों में भारत की प्रजनन दर में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। आज, एक औसत भारतीय महिला के जीवनकाल में उसके 2.2 बच्चे होने की अपेक्षा की जाती है जो कि ऐसी प्रजनन दर है जो संयुक्त राज्य अमरीका (1.6) जैसे कई आर्थिक रूप से उन्नत देशों की दरों से थोड़ा ही ज़्यादा है, और भारत की 1992 (3.4) और 1950 (5.9) की दर की तुलना में बहुत कम है।[1]

बहुसंख्यक हिंदू और मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यक समूहों सहित देश के हर धार्मिक समूह में प्रजनन क्षमता में गिरावट देखी गई है। मुसलमानों में, उदाहरण के लिए, कुल प्रजनन दर में भारी गिरावट देखी गई है, 1992 में प्रति महिला 4.4 बच्चों से 2015 में 2.6 बच्चे,जो कि सबसे हाल का वर्ष है जिसके लिए भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से धर्म संबंधी डेटा उपलब्ध है।

भारत के प्रमुख धार्मिक समूहों में मुसलमानों की प्रजनन दर अभी भी सबसे अधिक है, उसके बाद हिंदुओं की, जो कि

भारत में, प्रजनन दरों में गिरावट आई है और धार्मिक अंतर कम हुए है।

भारत में एक औसत महिला के जीवनकाल में उससे अपेक्षित बच्चों की संख्या

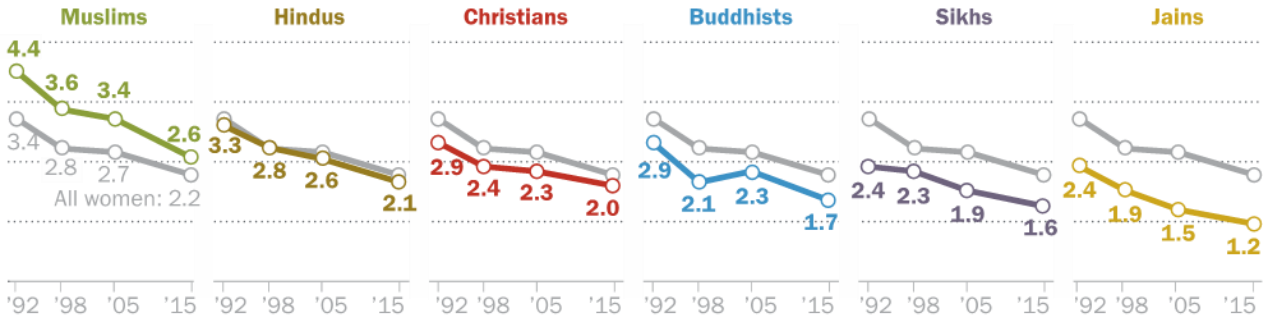

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 1992-2015.
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW रिसर्च सेंटर

2.1 है। जैनियों की प्रजनन दर सबसे कम है (1.2)। सामान्य पैटर्न काफी हद तक वैसा ही है जैसा की यह 1992 में था, जब मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे अधिक 4.4 थी और उसके बाद हिंदुओं की, जो कि 3.3 थी। लेकिन, **भारत के धार्मिक समूहों के बीच प्रजनन क्षमताओं में जो अंतर हैं, वे जितना हुआ करते थे उसकी तुलना में बहुत कम हैं।**

[1] जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, तब तक इस पूरी रिपोर्ट में कुल प्रजनन दर (TFR) का उपयोग करके ही प्रजनन क्षमता को मापा जाता है। कुल प्रजनन दर, एक औसत महिला द्वारा अपने जीवनकाल में पैदा किए जा सकने वाले बच्चों की कुल संख्या है यदि प्रजनन पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आता है। TFRएक निश्चित अवधि (उदाहरण के लिए, पिछला वर्ष) के दौरान प्रत्येक आयु वर्ग की महिलाओं द्वारा अनुभव की गई जन्म दरों का योग करके अभिकलित की जाती है। दूसरे शब्दों में, TFR एक स्थान और समय में प्रजनन पैटर्न का एक चित्रण है। INSTEAD OF TRANSLITERATION FOR SNAPSHOP CAN WE SAY PICTURE (CHITR)

उदाहरण के लिए, जबकि1992 में एक मुस्लिम महिलाओं से एक हिंदू औरत की तुलना में औसतन 1.1 अधिक बच्चे होने की अपेक्षा की जाती थी, 2015 में यह अंतर कम हो कर 0.5 हो गया।

भारत की धार्मिक संरचना के लिए इन प्रवृत्तियों का क्या अर्थ है? प्रजनन दर में भिन्नताओं की वजह से भारत की मुस्लिम आबादी अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में कुछ तेजी से बढ़ी है। लेकिन आंशिक रूप से प्रजनन पैटर्न में गिरावट और अभिसरण के कारण, **1951 के बाद से, जब भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहली जनगणना की थी, जनसंख्या की समग्र धार्मिक संरचना में केवल मामूली परिवर्तन हुए हैं।**

सबसे हाल ही की, 2011 में की गई जनगणना में भारत के 120 करोड़ कुल निवासियों में 79.8% हिंदू थे। जो कि 2001 में हुई पिछली जनगणना की तुलना में 0.7 प्रतिशत अंक कम है, और 1951 में दर्ज किए गए 84.1% से 4.3 प्रतिशत

हिंदू अभी भी भारत में बहुसंख्यक हैं, जबकि मुसलमानों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी है

% भारतीय जो ... हैं

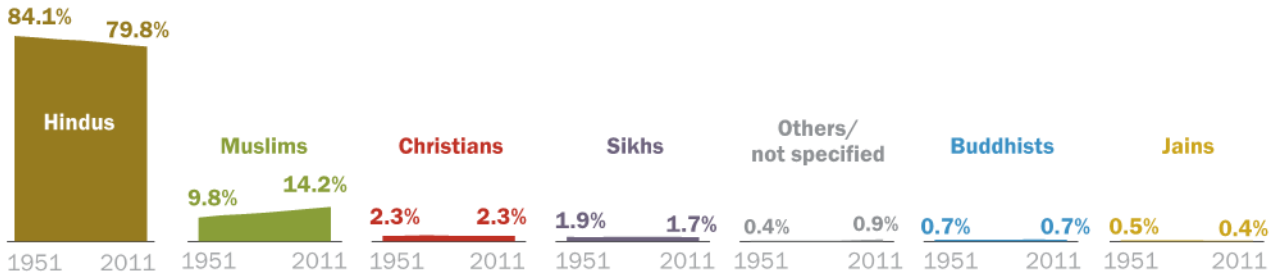

स्रोत: भारत की जनगणना, 1951-2011.
"भारत की धार्मिक संरचना"
PEW रिसर्च सेंटर

अंक कम है। इस बीच, मुसलमानों का प्रतिशत 2001 में 13.4% से बढ़कर 2011 में 14.2% हो गया - 1951 से 4.4 प्रतिशत अंक ऊपर। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, जो कि कुल मिलाकर शेष लगभग 6% आबादी है, अपने हिस्सों में सापेक्ष रूप से स्थिर रहे हैं।[2]

दशकों से, जनसंख्या वृद्धि दरें काफी धीमी हो गई हैं - समग्र रूप से और विशेष रूप से मुसलमानों में। इसकी प्रजनन दर में तीव्र गिरावट से पहले, भारत एक ऐसे प्रक्षेपवक्र पर था जिसके परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या बहुत अधिक होती, और साथ ही धार्मिक आबादी के वितरण में भी एक बड़ा बदलाव होता। (अध्याय 1 में वृद्धि दर से संबंधित चर्चा देखें।)

जबकि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन मामूली रहे हैं, तब भी उन्हें पूरे भारत में समान रूप से वितरित नहीं किया गया है। कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अन्य राज्यों या पूरे देश की तुलना में अधिक तीव्र जनसंख्या वृद्धि या धार्मिक संरचना में अधिक बड़ें बदलाव अनुभव किए हैं। उदाहरण के लिए, 2001 से 2011 के बीच अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं

[2]जनसंख्या के ये हिस्से, भारत की 1951 जनगणना, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना थी, और सबसे हाल ही में, 2011 में हुई जनगणना पर आधारित है। अगली जनगणना 2021 की शुरुआत में होनी निर्धारित थी, लेकिन लिखते समय तक कोरोनावायरस महामारी के कारण यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। जनगणना में कुछ अल्पसंख्यक धर्मों को कम रिपोर्ट किया गया हो सकता है। विवरणों के लिए कार्य-विधि देखें।

के प्रतिशत में लगभग 6% की गिरावट हुई लेकिन पंजाब में इनकी संख्या लगभग 2% बढ़ गई। (भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की धार्मिक जनसांख्यिकी पर अधिक जानकारी के लिए अध्याय 3 देखें।)

ये PEW रिसर्च सेंटर के भारत की जनगणना और अन्य स्रोतों से मिले डेटा के जनसांख्यिकीय विश्लेषण के प्रमुख निष्कर्षों में से हैं और इसे डिज़ाइन किया गया है एक महत्वपूर्ण नए सर्वेक्षण, "भारत में धर्म: सहिष्णुता और अलगाव" के पूरक के रूप में जो कि जून 2021 में प्रकाशित किया गया था । यह विश्लेषण मुख्य रूप से भारत की स्वतंत्रता के बाद के रुझानों को देखता है, जो देश की धार्मिक जनसांख्यिकी में महत्वपूर्ण बदलावों के साथ था। ब्रिटेन के लंबे औपनिवेशिक शासन के अंत में 1947 में हुए देश के बँटवारे ने भारतीय उपमहाद्वीप को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया, जिससे लाखों मुसलमान एक नए राष्ट्र, पाकिस्तान में चले गए, जबकि लाखों हिंदू और अन्य धार्मिक समूहों के लोग नए भारत में बस गए (नीचे दिया गया साइडबार देखें)।

प्रजनन और धर्मांतरण के साथ साथ प्रवासन तीन मुख्य तंत्रों में से एक है जो धार्मिक समूहों के घटने या बढ़ने का कारण बनते हैं। लेकिन 1950 के दशक से, प्रवासन का भारत की धार्मिक संरचना पर केवल मामूली प्रभाव पड़ा है। भारत में रहने वाले 99% लोगों का जन्म भी भारत में ही हुआ है। भारत छोड़कर जाने वाले प्रवासी संख्या में आप्रवासियों से 3:1 के अनुपात में अधिक है, और हिंदुओं की तुलना में अल्पसंख्यक धर्म के लोगों की भारत छोड़कर जाने की संभावना अधिक है। धार्मिक परिवर्तन, या धर्मांतरण – जब कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म के लिए एक धर्म को छोड़ता है या किसी भी धर्म से सम्बद्ध होने से रुकता है – का भी भारत की समग्र संरचना पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता हुआ प्रतीत होता है; जिसमें 98% भारतीय वयस्क अभी भी उसी धर्म के साथ अभिज्ञात होते हैं जिसमें वे बड़े हुए हैं।

परिणामस्वरूप,**जनगणना और सर्वेक्षण के डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रजनन विभाजन के बाद के दशकों में हुए धार्मिक संरचना में मामूली बदलाव का अब तक का सबसे बड़ा चालक रहा है** (विवरण के लिए अध्याय 2 देखें)।[3]

प्रजनन दर से जुड़े कई कारणों में से धर्म केवल एक कारण है। जबकि यह रिपोर्ट भारत के मुख्य धार्मिक समूहों के प्रजनन पैटर्न में अंतरों का वर्णन करती है, तब भी यह इन पैटर्न पर होने वाले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के पूर्ण प्रभाव को माप नहीं सकती है और ना ही यह उस प्रत्यक्ष भूमिका की मात्रा निर्धारित कर सकती है जो धर्म निभाता है जब प्रजनन क्षमता और परिवार के आकार की बात आती है।

भारत में या अन्य देशों में, महिलाओं को होने वाले बच्चों की संख्या निर्धारित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य समृद्धि संकेतक – जैसे कि जीवन प्रत्याशा और संपदा का औसत स्तर – का भी प्रजनन उपायों से परस्पर संबंध होता है: उन महिलाओं के कम बच्चें होने की संभावना होती है जिन्हें बेहतर शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुई होती हैं।

जनसंख्या वृद्धि न केवल महिलाओं के कितने बच्चे हैं इस बात से, बल्कि प्रसव उम्र की महिलाओं की सघनता से भी प्रेरित होती है। युवा आबादी में अधिक महिलाएँ अपने प्रमुख प्रसव के वर्षों में प्रवेश करती हैं और इसके परिणामस्वरूप उसमें वृद्ध आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति है।

इसके अतिरिक्त, लोग भारत में कहाँ पर रहते हैं और साथ ही उनका इतिहास और सांस्कृतिक मानदण्ड (जिन्हें मापना अधिक कठिन होता है) पारिवारिक मामलों के बारे में उनके द्वारा किए जाने वाले विकल्पों में एक भूमिका निभाते हैं।

[3] 1947 के भारत के बँटवारे ने ज़मीन और नागरिकों को धर्म के आधार पर, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। पिछली शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर राष्ट्रीय और राज्य की सीमाएँ कैसे बदली हैं इसकी पृष्ठभूमि के लिए साइडबार देखें।

संक्षेप में, केवल लोगों का धर्म यह निर्धारित नहीं करता है कि उनके कितने बच्चे होंगे। धर्म तो केवल एक जटिल तस्वीर का बस हिस्सा है।

साइडबार: भारत का बदलता भूगोल

भारत की जनगणना 1881 से अपने धार्मिक समूहों के आकार पर डेटा प्रदान करती है। लेकिन देश की धार्मिक संरचना में हुए बदलावों का पूरी तरह से पता लगाना एक चुनौती है क्योंकि तब से देश की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ कई बार खिसक चुकी हैं। कई बड़े क्षेत्र स्वतंत्र देश बन गए है, जबकि और भारतीय राज्यों, रियासतों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकार और स्थिति बदल गई है।

सामान्यतया, भारत की *बाहरी* सीमाएँ 1947 के विभाजन के बाद से इतनी स्थिर रही हैं कि 1951 से राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों की तुलना की जा सके। हालाँकि, 1950 के दशक से भारतीय राज्यों की *आंतरिक* सीमाएँ इतनी बार बदली हैं कि राज्य स्तरीय आँकड़ों की विश्वसनीय तुलनाएँ केवल 2001-2011 के दशक के लिए ही संभव हैं।

भारत का बँटवारा

भारतीय जनगणना शुरू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक परिवर्तन 1947 का विभाजन था। औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्षों में, अंग्रेजों ने न केवल भारत को स्वतंत्रता देने की बल्कि उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी और उत्तरपूर्वी प्रांतों में मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को भी संप्रभुता प्रदान करने की माँगों का सामना किया था। परिणामस्वरूप, अंग्रेज़ी शासन को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने पाकिस्तान देश का भी निर्माण किया, जिसमें उस समय आज का बांग्लादेश भी शामिल था। अंग्रेज़ों को बँटवारे के बाद होने वाली जमसंख्या के स्थानांतरण और अराजकता की सीमा का अंदाज़ा नहीं था; जबकि खराब योजना ने अंतिम क्षणों में भ्रम पैदा किया जिसने परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानवीय संकट में योगदान दिया।

बँटवारा से शुरू से ही उथल-पुथल भरा रहा था। बँटवारे और स्वतंत्रता की तारीख को बिना किसी पूर्व सूचना के 10 महीनों आगे बढ़ा जून 1948 से अगस्त 1947 कर दिया गया। जुलाई 1947 तक भारत और पाकिस्तान की सीमाएँ परिभाषित करने वाली समिति नहीं बुलाई गई और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के दो दिन *बाद* इस समिति ने अपना निर्णय प्रकाशित किया। उस समय से पहले, अधिकांश लोगों केवल यह जानते थे कि विभाजन इस आधार पर होगा कि किसी दिए गए स्थान में कौन सा धार्मिक समूह बहुसंख्यक है।

मुसलमान नए स्वतंत्र पाकिस्तान में प्रवास कर गए, हिंदू और अन्य लोगों ने नए स्वतंत्र भारत में प्रवास किया। 1947 के अंत तक, व्यापक दंगों और हिंसा के बीच लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, और जिसने इतिहास का एक सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बनाया। कुछ अनुमानों के अनुसार, दस लाख से ज़्यादा लोग मारे गए।

राज्य और क्षेत्र

बँटवारे के बाद भारत की बाहरी और आंतरिक सीमाओं में कई परिवर्तन होते रहे। किसी न किसी तरह, इस रिपोर्ट के लेखन के समय मौजूद 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों में से अधिकांश को 1951 की ऐतिहासिक जनगणना के बाद से अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई।

भारत का आकार देखते हुए, बँटवारे के बाद बाहरी सीमाओं में आए बदलावों के कारण - गोवा जैसे छोटे क्षेत्रों को शामिल करने के बाद भी - जहाँ इसाई आबादी ज़्यादा है, - देश की धार्मिक जनसांख्यिकी में कुछ ख़ास परिवर्तन नहीं आए। कुछ बाहरी सीमाएँ बदल गईं क्योंकि पुर्तगाल और फ्रांस - जो शेष भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी कई वर्षों तक इस क्षेत्र पर रहे थे - इस क्षेत्र से हट गए। 1961 में पश्चिमी तट पर पुर्तगाल द्वारा शासित गोवा पर भारत ने कब्जा कर लिया और 1971 से इसे भारत की जनगणना में शामिल किया गया, शुरू में एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में और बाद में एक राज्य के रूप में। पुडुचेरी (जिस पर पहले फ्रांस की हुकुमत थी), जो भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है, 1962 में भारत का केंद्रशासित प्रदेश बन गया। 1975 में, सिक्किम के लोगों ने, जो कि उस समय चीन की सीमा से लगाा एक स्वतंत्र देश था, मतदान देकर सिक्किम को भारत का 22वाँ राज्य बनाया।

दूसरी ओर, स्वतंत्रता के बाद से भारत की आतंरिक सीमाएँ निरंतर प्रवाह में रही हैं, जिससे राज्यों के भीतरधार्मिक संरचना में भी बारंबार बदलाव रहे हैं। केवल पिछले 50 सालों में ही एक दर्जन नए राज्यों का निर्माण हुआ: तेलंगाना का निर्माण, जो कि भारत का सबसे नया राज्य है, 2014 में हुआ। 2019 में जम्मू और कश्मीर का, जो कि पहले एक एकीकृत राज्य था, दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठन किया गया। हालाँकि, 2001 और 2011 की जनगणनाओं के बीच आतंरिक सीमाओं में कोई प्रभावकारी बदलाव नहीं हुए। इस रिपोर्ट में इस अवधि का अध्ययन राज्य स्तर पर किया गया है। उस दशक के दौरान, भारत में कुल 35 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश थे।

1. जनसंख्या वृद्धि और धार्मिक संरचना

बँटवारे के बाद छह दशकों में भारत की जनसंख्या तीन गुना से अधिक बढ़ गई - 1951 की जनगणना में 36.1 करोड़ लोगों से 2011 में 120 करोड़ से अधिक हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार 2020 तक, भारत में हर महीने लगभग 10 लाख निवासी बढ़ रहे हैं, जिससे यह 2030 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।

1950 के दशक के बाद से भारत के सभी सबसे बड़े धार्मिक समूहों में काफी वृद्धि हुई है

प्रत्येक जनगणना वर्ष में धर्म के अनुसार व्यक्तियों की संख्या (करोड़ में)

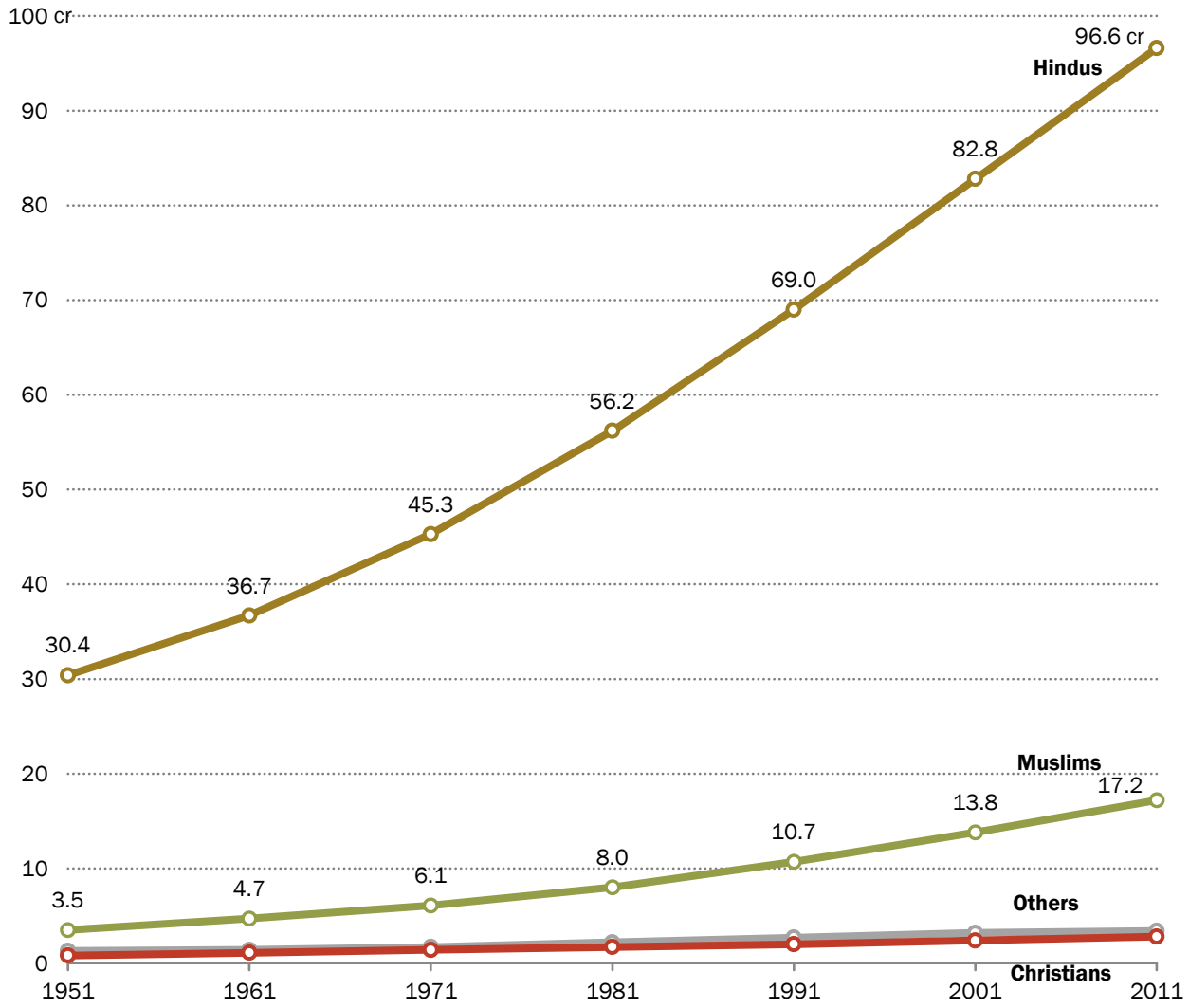

ध्यान दें: "अन्य" में बौद्ध, सिख, जैन, छोटे धार्मिक समूहों के अनुयायी और बिना धार्मिक सम्बद्धता वाले लोग शामिल है।
स्रोत: भारत की जनगणना, 1951-2011.
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW रिसर्च सेंटर

हालाँकि 1951 और 2011 के बीच धार्मिक समूह में असमान दर से वृद्धि हुई, भारत में हर प्रमुख धर्म की आबादी में वृद्धि देखी गई: उदाहरण के लिए, हिंदू 30.4 करोड़ से बढ़कर 96.6 करोड़ हो गए, मुसलमान 3.5 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़ हो गए और स्वयं को ईसाई कहने वाले भारतीयों की संख्या 0.80 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई।

हालाँकि, कुछ प्रमाण है कि ईसाई कम गिने जा सकते है। जो लोग अपने आप को जनगणना में ईसाई के रूप में बताते हैं, वे अपने आप को अनुसूचित जातियों का होना अभिज्ञात नहीं करवा सकते हैं (ऐतिहासिक रूप से जिन्हें 'दलित' या अपमानजनक शब्द "अछूत" के रूप में जाना जाता है)। अनुसूचित जाति के लोग सरकारी लाभों के लिए पात्र होते हैं, और कहा जाता है कि इससे जनगणना जैसे सरकारी फॉर्म भरते समय इस श्रेणी के कुछ लोग स्वयं को हिंदू के रूप में अभिज्ञात करवाते हैं।[4] 2015 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में - जो कि एक बड़ा, उच्च-गुणवत्ता का पारिवारिक सर्वेक्षण है जो ईसाइयों को अनुसूचित जाति से अलग नहीं करता है - साक्षात्कार लिए गए 21% ईसाइयों ने कहा कि वे अनुसूचित जाति के हैं।

[4] इस घटना की चर्चा कुमार एम, अशोक और रोवेना रोबिनसन में की गई है 2010। " Legally Hindu: Dalit Lutheran Christians of Coastal Andhra Pradesh" रोबिनसन, रोवेना और जोसफ मारियानस कुजुर, संपादक में " Margins of Faith: Dalit and Tribal Christianity in India")

भारत की जाति व्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन

भारत में, जातियाँ वंशानुगत सामाजिक वर्ग हैं। ऐतिहासिक रूप से, जिस जाति में किसी व्यक्ति का जन्म होता था वही जाति सामाजिक पदानुक्रम में उसकी स्थिति का और साथ ही वह किन लोगों के साथ सामाजिक संबंध बना सकता है और कौनसा पेशा चुन सकता है इस बात का स्थायी रूप से निर्धारण करती थी।

जाति के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास में, सरकार ने एक सकारात्मक योजना बनाई जिसे "आरक्षण" के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालय में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, 7.5% अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और 27% "अन्य पिछडे वर्ग" (ओबीसी) के लोगों के लिए आरक्षित करता है।

तीन-चौथाई भारतीय ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग के हैं।

धर्म के अनुसार वर्ग श्रेणी में %

	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जनजातियाँ	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल
बौद्ध	88%	9%	1%	98%
हिंदू	23	10	44	77
ईसाई	21	29	26	76
मुस्लिम	3	2	55	60
सिख	38	0	19	57
जैन	3	0	12	15
सभी	21	10	44	75

ध्यान दें: "सभी" में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, छोटे धार्मिक समूहों के अनुयायी और बिना किसी धार्मिक सम्बद्धता वाले लोग शामिल है।
स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015।
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW रिसर्च सेंटर

अनुसूचित जातियों में, जिन्हें दलित (या अपमानजनक शब्द "अछूत") के रूप में जाना जाता है, ऐसे समूह शामिल हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से बहिष्कृत किया जाता था और जिन्हें मछली पकड़ने, मैला ढोने और सीवर की सफाई जैसे "प्रदूषणकारी" व्यवसायों में लगाया जाता था। अनुसूचित जनजातियाँ स्वदेशी लोग हैं। ओबीसी वर्ग के लोगों को वंशानुगत रूप से अन्य सामाजिक वर्ग की पहचान मिली जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित हैं।

संविधान के अंतर्गत, मुसलमान और ईसाई, हिंदुओं और अन्य लोगों के लिए उपलब्ध अधिकांश जाति-आधारित आरक्षणों के लिए पात्र नहीं हैं। यह मुद्दा विविदास्पाद है। लाभों तक अधिक से अधिक पहुँच की अनुमति देने के लिए कानून बदलने के समर्थक इंगित करते है कि वंचित लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के आशय के कार्यक्रमों से इन समूहों को वर्जित करने से धर्म-आधारित असमानताएँ बढ़ती हैं, और यह अनिवार्य रूप से कुछ लोगों के लिए जाति व्यवस्था को संरक्षित करता है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था के समर्थक इन समूहों की ओबीसी स्थिति के आधार पर आरक्षण प्राप्त करने की योग्यता और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले लाभों को उजागर करते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश भारतीय परिवार (75%) ऐसी जाति श्रेणी में आते हैं जो सरकारी आरक्षण के लिए पात्र है, लेकिन यह संख्या धार्मिक संबद्धता के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न है, जो जैनों में 15% से ले कर बौद्धों के लिए 98% की सीमा में है। लगभग तीन-चौथाई (76%) ईसाई ऐतिहासिक रूप से वंचित जाति के हैं, जिनमें 21% वे शामिल हैं जो स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य कहते हैं। हालाँकि, भारतीय जनगणना में, ईसाई स्वयं की पहचान अनुसूचित जातियों के रूप में नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनगणना में ईसाई कम गिने जा सकते हैं।

उसी सर्वेक्षण में, मुसलमानों के छोटे हिस्सों ने स्वयं की पहचान अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में की है, लेकिन आधे से अधिक ने कहा कि वे ओबीसी के सदस्य हैं।

20वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या में वृद्धि एक आर्थिक रूपांतरण साथ हुई जो जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर और खाद्य उत्पादन में कई महत्वपूर्ण सुधार लाई। किंतु विशेषज्ञों के बीच एक आम सहमति है कि भारत का आर्थिक विकास आंशिक रूप से स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा और प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण बाधित हुआ है। 1950 के दशक से, भारतीय सरकार ने गर्भनिरोधक उपायों से लेकर अनिवार्य नसबंदी तक, कई जन्म नियंत्रण विधियों को बढ़ावा देने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम किया है। आज कल, कुछ राज्य और प्रदेश बड़े परिवारों को दंडित करके अधिक बच्चे पैदा करने के लिए हतोत्साहित करते हैं, जैसे कि दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिताओं पर सामाजिक सेवाओं को प्राप्त करने या किसी भी राजनीतिक पद को धारण करने पर प्रतिबन्ध लगाना। 2017 में, भारत के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुधार करके, गर्भनिरोधक उपाय और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा पहुँच प्रदान करा कर, विशेष रूप से अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दरों वाले क्षेत्रों में, 2025 तक प्रजनन क्षमता को प्रतिस्थापन स्तर तक नीचे लाना था ।[5]

आंशिक रूप से इन उपायों के कारण, आबादी विस्तार धीमा हुआ है, विशेषरूप से 1990 के दशक से। 1960 के दशक में और पुनः 1970 के दशक में लगभग 25% बढ़ने के उपरान्त, 2001-2011 दशक की जनगणना में वृद्धि में 20% की गिरावट आई।

भारत की जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत तेजी से धीमी हुई है, विशेषरूप से 1990 के दशक के बाद से

जनगणना के वर्षों के बीच भारत के जनसंख्या आकार में % वृद्धि

	सभी	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई
1951-61	21.6%	20.7%	32.7%	29.0%
1961-71	24.8	23.7	30.9	33.0
1971-81	24.7	24.0	30.7	17.0
1981-91	23.9	22.7	32.9	17.8
1991-2001	21.5	19.9	29.4	22.6
2001-11	17.7	16.7	24.7	15.7

स्रोत: 1951-2011 भारतीय जनगणना डेटा का PEW रिसर्च सेंटर का विश्लेषण "भारत की धार्मिक संरचना"

PEW रिसर्च सेंटर

भारत के सभी प्रमुख धार्मिक समूहों के वृद्धि दर में गिरावट आई है, किन्तु धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच यह गिरावट अधिक स्पष्ट है, जिन्होंने पहले के दशकों में हिंदुओं को पीछे छोड़ दिया था।। 1951 और 1961 के बीच, मुसलमानों की आबादी में 32.7% का विस्तार हुआ, जो भारत की कुल दर 21.6% से 11 प्रतिशत अंक अधिक थी। लेकिन अब ये अंतर कम हो गया है। 2001 से 2011 तक, मुसलमानों (24.7%) और कुल भारतीयों (17.7%) के बीच वृद्धि में अंतर 7 प्रतिशत अंक था। सबसे हाल ही के जनगणना दशक में भारत की ईसाई आबादी तीन सबसे बड़े समूहों में सबसे धीमी गति से बढ़ी है – 2001 और 2011 के बीच 15.7% की वृद्धि प्राप्त की, यानी कि बँटवारे के बाद के दशक में दर्ज की गई दर (29.0%) की तुलना में वृद्धि दर में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई।

[5] इस रिपोर्ट में प्रजनन की मानक माप, कुल प्रजनन दर (TFR) है। जन्म के समय प्राकृतिक लिंगानुपात और कम मृत्यु दर वाले देशों में, प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर प्रत्येक पीढ़ी के प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त है। भारत में, जन्म के समय लिंगानुपात विकृत है (अध्याय 2 में "प्रजनन और शिक्षा, अर्थव्यवस्था और स्थान से इसके संबंध" अनुभाग देखें) और समृद्ध देशों की तुलना में छोटे बच्चों की मृत्यु होने की दर अधिक है। परिणामस्वरूप, प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक प्रजनन स्तर 2.1 से ज़्यादा है। प्रजनन की प्रतिस्थापन दर में कुछ भिन्नताएँ देशों के भीतर भी होती हैं – क्षेत्रों या धार्मिक समूहों के बीच सहित -- जब जन्म और मृत्यु के लिंगानुपात असमान होते हैं।

निरपेक्ष संख्या में, देश के सभी सबसे बड़े धार्मिक समूह अभी भी कई लाखों अनुयायी प्राप्त कर रहे हैं। जनगणना के बीच के सबसे हाल के दशक में, हिंदुओं में 13.8 करोड़ लोग जुड़े, जबकि मुसलमानों में 3.4 करोड़ की वृद्धि हुई। उस

समय पर भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 20.00 करोड़ की वृद्धि हुई, जो 2001 में लगभग 100 करोड़ से बढ़कर 2011 में 120 करोड़ हो गई।

2015 PEW रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के लगभग 94% हिंदू अब भारत में रहते हैं, जो नेपाल के साथ साथ हिंदू बहुमत वाले केवल दो देशों में से एक है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में से एक का घर भी है, सिर्फ इंडोनेशिया भारत से आगे है, जिसमें 2010 में 20.9 करोड़ मुस्लिम थे। पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी लगभग भारत की मुस्लिम आबादी जितनी ही है। 13.4 करोड़ मुसलमानों के साथ बंगलादेश चौथे स्थान पर है। (बँटवारे के समय आज का बंगलादेश पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन 1970 के दशक में यह पाकिस्तान से अलग हो गया।) पाकिस्तान और बंगलादेश दोनों ही मुस्लिम बहुल है, लेकिन इन देशों की कुल आबादी भारत की आबादी से बहुत कम है।

बँटवारे के बाद से भारत की धार्मिक संरचना काफी हद तक स्थिर है।

प्रतिशत में कहा जाए, तो भारत के छः सबसे बड़े धार्मिक समूह बँटवारे के बाद से अपेक्षाकृत स्थिर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव रहा है मुसलमानों की संख्या में हल्की वृद्धि और साथ ही हिंदुओं की संख्या में अनुरूपी गिरावट। 1951 और 2011 के बीच, मुसलमान 4.4 प्रतिशत अंक बढ़कर जनसंख्या का 14.2% हिस्सा हो गए, जबकि हिंदू 4.3 प्रतिशत अंक घटकर 79.8% हो गए।

1951 के बाद से प्रत्येक जनगणना में भारत की आबादी में ईसाई 2% से 3% के बीच रहे हैं। यद्यपि, इस बात की चिंताएँ हैं कि ईसाई कम गिने जा सकते हैं, फिर भी इस कम गणना की सीमा और समय के साथ यह कैसे बदल रही होगी इसे निर्धारित करना कठिन है।[6]

[6] PEW रिसर्च सेंटर की पूर्व की रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया था कि 2010 में भारत की ईसाई आबादी, जनगणना एजेंसी द्वारा दर्ज की गई 2.3% के बजाय, 2.6% होगी, यह मानकर की यह गिनती 10% कम है। (उदाहरण के लिए, 2011 की रिपोर्ट का परिशिष्ट A"वैश्विक ईसाई धर्म" देखें हालाँकि, समय के साथ संभावित कम गिनती का अनुमान लगाने में कठिनाई होने के कारण, इस रिपोर्ट में प्रकाशित आँकड़े जनगणना एजेंसी से प्राप्त असमायोजित आँकड़े हैं।

बँटवारे के बाद से, भारत की आबादी के प्रतिशत के रूप में हिंदुओं के लिए मामूली गिरावट और मुसलमानों के लिए थोड़ी वृद्धि

प्रत्येक जनगणना वर्ष में धर्म के अनुसार लोगों का %

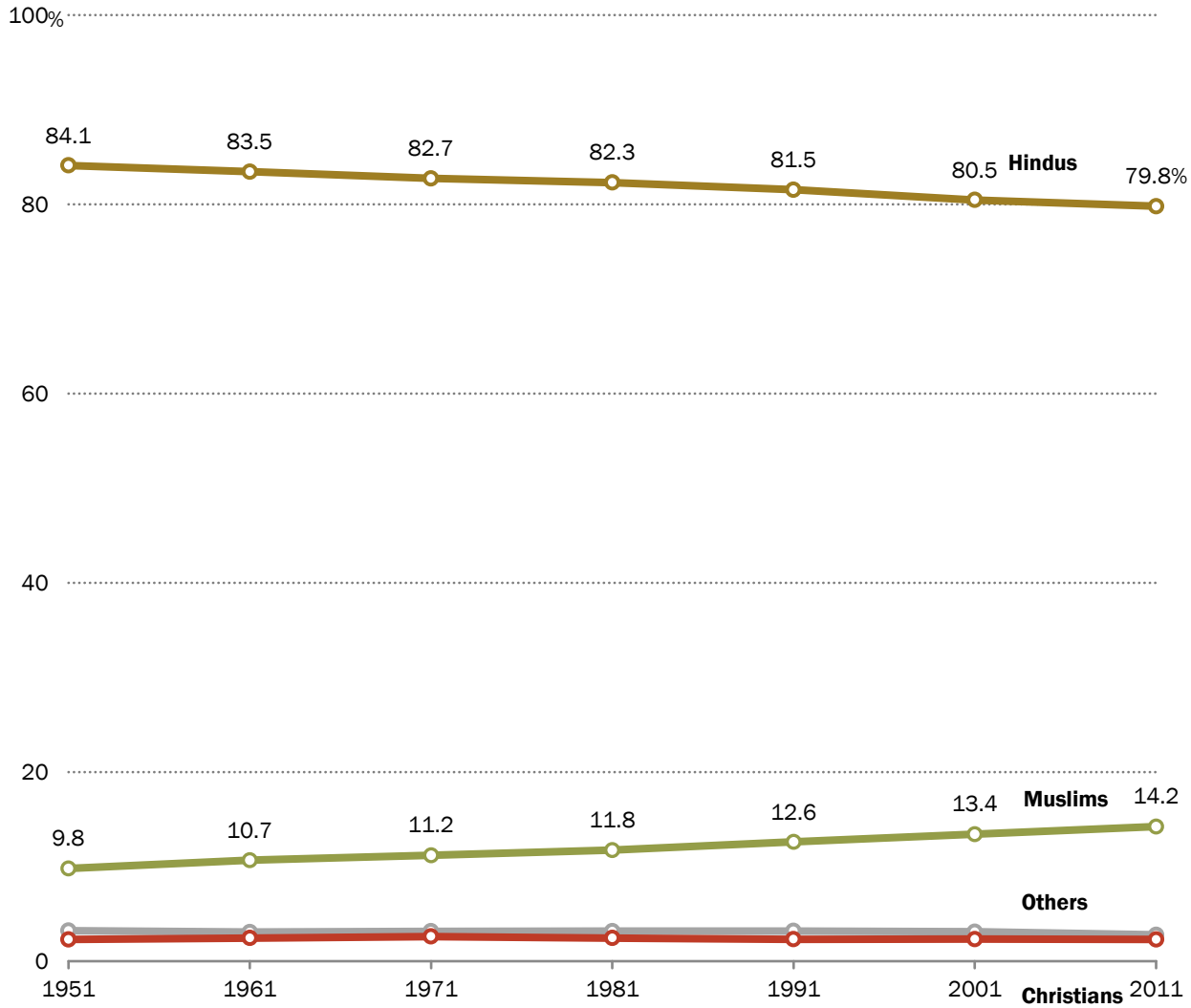

ध्यान दें: "अन्य" में बौद्ध, सिख, जैन, छोटे धार्मिक समूहों के अनुयायी और बिना किसी धार्मिक सम्बद्धता वाले लोग शामिल है।
स्रोत: भारत की जनगणना, 1951-2011.
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर**

3% भारतीय जो हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्म के साथ पहचान करते हैं, स्वतंत्रता के बाद के दशकों में उनकी संख्या बढ़कर करोड़ों में हो गई है। भारत की जनसंख्या का एक निरंतर हिस्सा रहते हुए (केवल 2% से कम), सिख, जो कि भारत के सबसे बड़े समूहों में से चौथा है, 1951 में 70 लाख से बढ़कर 2011 में 2.1 करोड़ हो गए। बौद्ध और जैन में भी यही पैटर्न दिखाई देता है – दशकों में उनकी संख्या दोगुनी या तिगुनी हो गई है, लेकिन कुल आबादी के जितने हिस्से का वे प्रतिनिधित्व करते हैं वह स्थिर रहा है, दोनों 1% से कम हैं।

बँटवारे के बाद से धार्मिक समूहों का भौगोलिक विभाजन भी अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। ईसाईयों की सबसे बड़ी संख्या अभी भी भारत के दक्षिणी राज्यों, केरल और तमिलनाडु में संकेन्द्रित हैं, और उनकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा छोटे पूर्वोत्तर राज्यों में है जो चीन, भूटान, बर्मा (म्यांमार) और बंगलादेश की सीमाओं से लगे हुए हैं। लक्षद्वीप के विरल आबादी वाले द्वीपसमूह को छोड़कर, पाकिस्तान से सटा, जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकीअधिकांश आबादी मुस्लिम है। बौद्ध और जैन धर्म के लोग अक्सर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, और सिख, भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्य पंजाब में पाए जाते हैं, जहाँ वे बहुसंख्यक हैं। लगभग हर अन्य राज्य और प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। (भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धार्मिक जनसांख्यिकी के बारे में और जानकारी पाने के लिए अध्याय 3 देखें)।

भारत कई सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों का घर है।

जनगणना के वर्ष के अनुसार संख्याएँ और हिस्से

संख्याएँ	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
सिख	68,20,000	78,50,000	1,03,80,000	1,30,90,000	1,64,30,000	1,92,20,000	2,08,30,000
बौद्ध	26,70,000	32,60,000	39,10,000	47,60,000	64,80,000	79,60,000	84,40,000
जैन	16,60,000	20,30,000	26,10,000	32,20,000	33,60,000	42,30,000	44,50,000
अन्य/निर्दिष्ट नहीं है	15,50,000	19,10,000	22,20,000	28,90,000	37,00,000	73,70,000	1,08,10,000
हिस्सा							
सिख	1.9%	1.8%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.7%
बौद्ध	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.8%	0.8%	0.7%
जैन	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%
अन्य/निर्दिष्ट नहीं है	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.7%	0.9%

स्रोत: भारत की जनगणना, 1951-2011.
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW रिसर्च सेंटर

2011 की जनगणना में लगभग 80 लाख लोगों ने कहा कि वे इन छः सबसे बड़े धार्मिक समूहों के किसी भी धर्म के नहीं हैं। इनमें से लगभग सभी लोग स्वेच्छा से किसी और धर्म से सम्बद्ध थे; केवल 30,000 भारतीयों ने स्वयं को नास्तिक बताया।

भारत की जनगणना में धर्म संबंधी प्रश्न ओपन-एंडेड है, जिसका अर्थ है कि लोग अपने पसंद का कोई भी जवाब दे सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन के अलावा, 2011 की जनगणना में 83 छोटे-छोटे धार्मिक समूह हैं जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 100 स्व-घोषित अनुयायी थे। इस श्रेणी के अंतर्गत, अधिकांश लोग आदिवासी या देशज धर्म के हैं। 50 लाख अनुयायियों के साथ, सरना अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, जिसके बाद गोंड (लगभग 10 लाख) और फिर सारी धर्मा (5,10,000) आता है।

भारत के पारसी (जो फारस में जोरास्ट्रियन के साथ अपनी वंशावली समझते हैं) इस मामले में असामान्य हैं कि उनकी आबादी में विभाजन के बाद से पूर्ण संख्या में गिरावट आई है, यहाँ तक कि जबकि कुल आबादी में उछाल आया है। इस प्रवृत्ति के लिए बड़े पैमाने पर समूह की उच्च औसत आयु और कम प्रजनन दर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है - जितने भारतीय पारसी पैदा हो रहे हैं उससे अधिक मर रहे हैं। 1951 में, वे पहले से ही लगभग 1,10,000 अनुयायियों के साथ थोड़े से अल्पसंख्यक थे; तब से उनकी संख्या लगभग आधी हो गई है।

भारत में छोटे धार्मिक समूह

2011 में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन के अलावा भारत के अन्य धार्मिक समूहों के लोगों की संख्या

सरना	49,60,000
गोंड/गोंडी	10,30,000
सारी धर्मा	5,10,000
डोन्यी पोलो/ साई डोन्यी पोलो	3,30,000
सनामाही	2,20,000
खासी	1,40,000
आदी बस्सी	90,000
नियामत्रे	80,000
आदि धर्म	80,000
पारसी/जोरास्ट्रियन	60,000
आदिम धम्म	60,000
नास्तिक	30,000

स्रोत: भारत की जनगणना 2011 "भारत की धार्मिक संरचना"

PEW रिसर्च सेंटर

जनगणना के अनुसार भारत में यहूदियों और बहाइयों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक के 4,000 से 5,000 के बीच अनुयायियों के साथ किया जाता है।

2050 तक आगे देखते हुए

प्रकाशन के दिन तक, कोरोनावायरस महामारी के कारण भारत की 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई है, और हो सकता है कि जनगणना के बाद कई वर्षों तक इसके परिणाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हों। हालाँकि, 2015 में PEW रिसर्च सेंटर ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समूहों के लिए जनसांख्यिकीय अनुमान प्रकाशित किए जो 2050 तक के लिए विस्तारित हैं। उस अनुमान के अनुसार, 2020 तक भारत लगभग 140 करोड़ लोगों का घर था।

भारत की आबादी के प्रक्षेप पथ में बहुत अधिक परिवर्तनों को छोड़कर, आगामी दशकों में भारतीय आबादी के एक हिस्से के रूप में मुसलमानों का धीरे-धीरे बढ़ते रहने अपेक्षित है जबकि हिंदुओं का एक बड़ा बहुमत रहेगा।

अनुमानित परिदृश्य में, 2020 तक लगभग 15% भारतीय मुस्लिम हैं (बनाम 2011 की जनगणना में 14.2%), 79% हिंदू हैं (बनाम 2011 में 79.8%), और 2% ईसाई हैं (2011 के समान)। 2050 में, हिंदुओं के लगभग 77% का भारतीयों में, मुसलमानों के 18% का और ईसाइयों के अभी भी 2% का प्रतिनिधित्व करने का अनुमान है। बौद्ध, सिख और जैन सभी की प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं और इसलिए आबादी में इनके प्रतिशत का सिकुड़ने का अनुमान है।

भारत में दुनिया के सबसे बड़े धर्मों की जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या अनुमान, 2010-2050

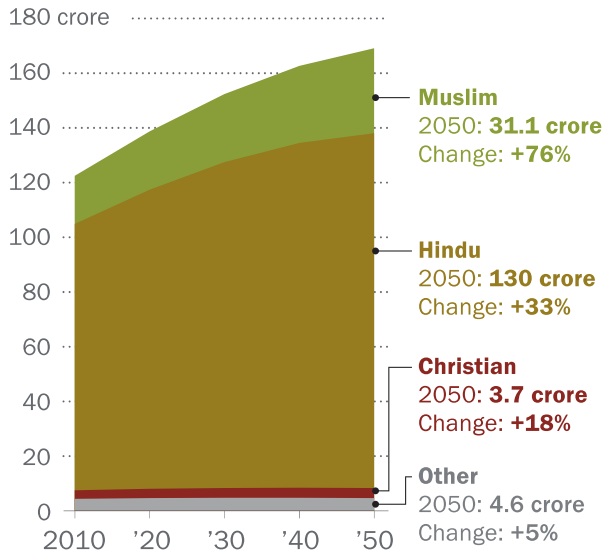

ध्यान दें: "अन्य" में बौद्ध, सिख, जैन, छोटे धार्मिक समूहों के अनुयायी और बिना किसी भी धार्मिक सम्बद्धता लोग शामिल है।
स्रोत: Pew रिसर्च सेंटर, "विश्व धर्मों का भविष्य: "जनसंख्या वृद्धि अनुमान, 2010-2050।"
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर**

2. धार्मिक परिवर्तन के कारण

वैश्विक जनसंख्या की धार्मिक संरचना हमेशा प्रवाह में रहती है। उदाहरण के लिए, कम औसत प्रजनन दर की वजह से दुनिया भर में बौद्धों की हिस्सेदारी संकुचित हो रही है, और संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिमी यूरोप में ईसाई कम हो रहे हैं क्योंकि अधिकाधिक लोग संगठित धर्म को छोड़ रहे हैं। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ धार्मिक आबादी के आकार में परिवर्तनों के लिए तीन मुख्य कारणों को जिम्मेदार ठहराते हैं:

- प्रजनन दरें
- धार्मिक परिवर्तन (या धर्मांतरण)
- प्रवासन

परिवर्तन के कारण: प्रजनन

भारत में जनसंख्या परिवर्तन की मुख्य प्रेरक प्रजनन दरें हैं। बँटवारे के बाद के कई दशकों में, एक औसत महिला के जीवनकाल में पैदा हुए उसके बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, और धार्मिक समूहों के बीच के अधिकांश अंतर कम हो गए हैं। हालाँकि, धार्मिक समूहों के बीच कुछ हद तक प्रजनन संबंधी अंतर अभी भी कायम हैं। कुल मिला कर, भारत में एक औसत महिला जीवनकाल में उसके 2.2 बच्चे होने की अपेक्षा की जाती है। औसतन हिंदू महिलाओं के 2.1 बच्चे होने की अपेक्षा की जाती है, जबकि मुस्लिम महिलाओं के 2.6 और ईसाई महिलाओं के 2.0 बच्चे होने की अपेक्षा की जाती है।

धार्मिक परिवर्तन में आयु संरचनाओं और जीवन प्रत्याशा की भूमिका

प्रजनन दर से संबंधित, भारत के सबसे बड़े धार्मिक समूह अपने आयु वितरणों में भिन्न हैं। 2020 तक, PEW रिसर्च सेंटर के अनुमान हैं कि मुसलमानों की 24 और ईसाइयों की 31 की तुलना में हिंदुओं की औसत (मीडियन) आयु 29 है। भारत के अन्य धार्मिक समूहों की संयुक्त औसत आयु 34 है। युवा आबादी वाले समूहों में अधिक महिलाएँ हैं जो अपने आरंभिक प्रजनन वर्षों में प्रवेश कर रही हैं और उनसे वृद्ध आबादियों की तुलना मेंअधिक तेज़ी से वृद्धि होने की अपेक्षा की जाती है। इससे वह बन सकता है जिसे जनसांख्यिकी विशेषज्ञ "जनसंख्या गति (पॉप्युलेशन मोमेंटम)" कहते हैं: उच्च प्रजनन दरें अपेक्षाकृत एक युवा आयु वितरण उत्पन्न करती हैं, जो फिर जनसंख्या वृद्धि की गति को बढ़ाता है। उसी तरह से, घटती प्रजनन दरें जनसंख्या वृद्धि पर ब्रेक के रूप में काम करती हैं।

सिद्धांततः, यदि कुछ समूह दूसरों की तुलना में अत्यधिक निम्न जीवन प्रत्याशा का सामना करते हैं, तो मृत्यु दरें भी धार्मिक समूहों के बदलते आकार में एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती हैं। लेकिन भारत में जीवन प्रत्याशा में धार्मिक अंतर मामूली होने अनुमानित हैं: ईसाई धर्म के लोगों की जीवन प्रत्याशा 68 है, उसके बाद मुसलमानों की (66) और हिंदुओं की (65) है।

इस बीच, शिशु मृत्यु दर में गिरावट का मतलब है कि माता-पिता अब कम जन्मों के साथ वांछित पारिवारिक आकार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बदले में भारत की प्रजनन दर को कम करने में और आगे धार्मिक समूहों के बीच वृद्धि के अंतर को कम करने में मदद की है।

प्रजनन और इसके शिक्षा, अर्थव्यवस्था और स्थान से संबंध

धार्मिक समूहों के भीतर, अनुयायीयों की कुछ जनसांख्यिकीय विशेषताएँ साझा करने की प्रवृत्ति होती हैं, जैसे कि शिक्षा के स्तर और घरेलू समृद्धि – और इनमें से कुछ कारक प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। अक्सर, ये साझा की गई विशेषताएँ किसी समूह के क्षेत्रीय केन्द्रीकरण से बँधी होती हैं। किसी स्थान को साझा करने का प्रायः अर्थ होता है कि स्थानीय सांस्कृतिक मानदंड के एक विशिष्ट समुच्चय को साझा करना, और परिवार के आकार के बारे में निर्णय उससे प्रभावित होते हैं जो पड़ोसियों, आस-पास के दोस्तों और परिवारों के बीच सामान्य और वांछित प्रतीत होते हैं। आर्थिक स्थितियाँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा (परिवार नियोजन संसाधनों सहित) तक पहुँच को प्रभावित कर सकती हैं, भी अलग-अलग जगह पर अलग-अलग हैं।

वैश्विक रूप से, किसी महिला का शिक्षा का स्तर उसके जीवनकाल में होने वाले उसके बच्चों की संख्या का सबसे अच्छा संकेतक है। उच्च शिक्षा आमतौर पर जननक्षम आयु से मेल खाती है, और इसके परिणामस्वरूप, उच्च शिक्षित महिलाएँ अक्सर बाद में शादी करती हैं और कम शिक्षा वाली महिलाओं की तुलना में बाद में उनका पहला बच्चा होता है। शिक्षा अक्सर महिलाओं को अधिक आर्थिक अवसर – जिसमें नौकरी भी शामिल है जिससे बच्चे के जन्म में और देरी हो सकती है – और बेहतर परिवार नियोजन संसाधन तक पहुँच प्रदान करती है। भारत में, महिलाओं को प्राप्त होने वाली शिक्षा के औसत वर्षों में बड़े पैमाने पर धार्मिक अंतर हैं; जिनमें ईसाई सबसे अधिक और मुस्लिम सबसे कम शिक्षा प्राप्त करती हैं।

धन एक अन्य कारक है जो दुनिया भर में प्रजनन क्षमता से जुड़ा है। गरीब महिलाओं में अधिक बच्चे होने की प्रवृत्ति है, न केवल इसलिए क्योंकि धन शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच से जुड़ा है, बल्कि इसलिए भी कि सीमित साधनों वाले घर में बच्चे श्रम और कमाई में योगदान कर सकते हैं। इसी तरह के कारणों से, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के अधिक बच्चे होते हैं। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाले धर्म के पैटर्न हमेशा एक ही दिशा में नहीं खींचते हैं। उदाहरण के लिए, औसतन भारतीय मुसलमान गरीब घरों में रहते हैं – एक ऐसी विशेषता जो उच्च जन्म दर से जुड़ी है। लेकिन समग्र भारतीयों की तुलना में मुसलमान शहरी क्षेत्रों में भी अधिक संकेन्द्रित हैं, जो एक ऐसी विशेषता है जो *कम* जन्म दर से जुड़ी है।

बेटों को वरीयता और बेटियों के प्रति घृणा भी समग्र प्रजनन क्षमता में एक भूमिका निभा सकती है। इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में कुछ माता-पिता अपनी बेटियों की संख्या को कम करने के लिए लिंग-चयनात्मक गर्भपात का सहारा लेते हैं – जिसके कारण 1970 और 2017 के बीच जितनी अपेक्षित थी, उसकी तुलना में, अनुमानित 2.07 करोड़ लड़कियाँ कम हैं – और कि प्रथा मुसलमानों और ईसाइयों की तुलना में भारतीय हिंदुओं में अधिक आम है।[7]

[7]चाओ, फेंग्किंग, पैट्रिक गरलैंड, एलेक्स आर. कुक और लियोनटाइन आलकेमा देखें। 2019. “Systematic Assessment of the Sex Ratio at Birth for All Countries and Estimation of National Imbalances and Regional Reference Levels.” (सभी देशों के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात का व्यवस्थित मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय असंतुलनों और क्षेत्रीय संदर्भ स्तरों का अनुमान) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही भलोत्रा, सोनिया, अभिषेक चक्रवर्ती और सेलीम गुलेसी भी देखें। 2020. “The Price of Gold: Dowry and Death in India." (भारत में दहेज़ और मृत्यु) जर्नल ऑफ़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स।

मध्य भारत में महिलाओं के अधिक बच्चे होने की प्रवृत्ति होती है हैं

राज्य के अनुसार, सभी महिलाओं की कुल प्रजनन दर

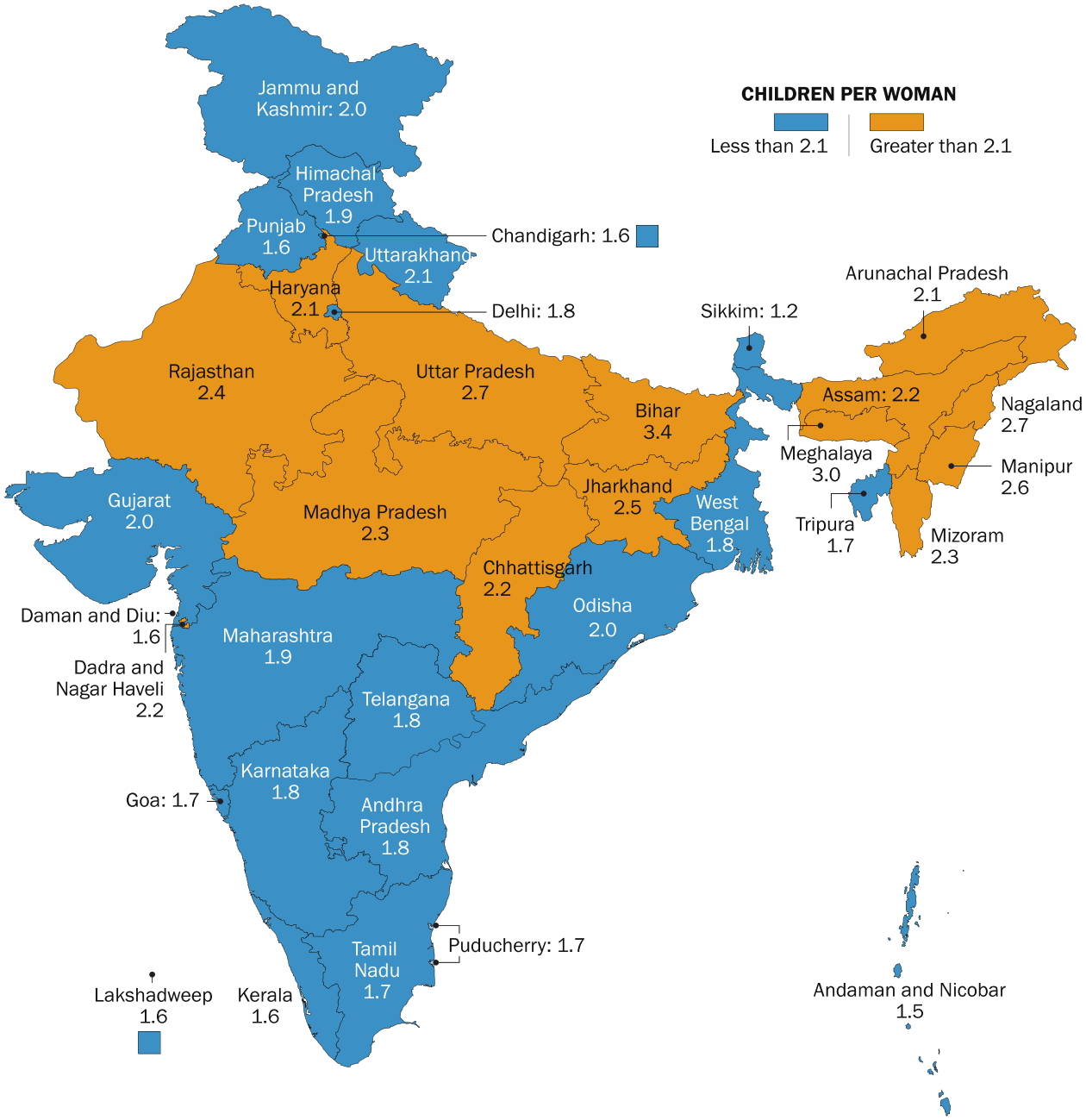

ध्यान दें: जम्मू और कश्मीर को अब दो प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, और दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली में विलय हो गया है।
स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015।
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर**

इन परस्पर जुड़े पैटर्न से कई सवाल खड़े होते हैं: क्या धार्मिक समूहों के बीच प्रजनन भिन्नताओं को धर्म के अलावा अन्य कारकों द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है? क्या धार्मिक पैटर्न केवल सहसंबंध के संयोग, और क्या ये एक अर्थपूर्ण विभेदक नहीं है? शायद मुस्लिम महिलाओं के अधिक बच्चे होने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि वे स्कूल में कम साल बिताती हैं और, औसतन, भारत में अन्य महिलाओं की तुलना में कम अमीर होती हैं, या क्योंकि बहुत से मुसलमान ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ *सभी* धर्मों की महिलाओं का परिवार बड़ा होता है।

वास्तव में, परिवार के आकार में कई कारकों का योगदान होता है, जिससे यह तय करना असंभव हो जाता है कि केवल धार्मिक सम्बद्धता से प्रजनन पर कितना प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और धन के स्तर के विपरीत, इनमें से कुछ कारक सांस्कृतिक या ऐतिहासिक होते हैं और इन्हें सर्वेक्षणों में आसानी से मापा नहीं जा सकता है।

हालाँकि, उपलब्ध डेटा का गहन सांख्यिकीय परीक्षण भारत में जिस तरह से प्रजनन क्षमता, शिक्षा, धन और निवास स्थान संबंधित हैं उस पर - और प्रजनन में धार्मिक अंतरों को इन कारकों द्वारा जिस हद तक समझाया जा सकता है उस पर प्रकाश डाला जा *सकता* है।

40 से 49 वर्ष तक की भारतीय महिलाओं के बीच समूह भिन्नताओं को नियंत्रित करना

प्रजनन क्षमता पर परस्पर संबंधित प्रभावों को अलग करने की कोशिश करने के लिए – और यह निर्धारित करने के लिए कि यदि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई एक ही स्थान पर रहते और उन्हें एक समान शिक्षा और धन प्राप्त होते तो क्या उनकी बच्चों की संख्या में फिर भी अंतर होता – शोधकर्ताओं ने एक बहुस्तरीय मिश्रित-प्रभाव मॉडल नामक सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया।

यह विश्लेषण उन महिलाओं के समूह पर ध्यान केंद्रित करता है जो 2015 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौरान 40 से 49 की उम्र की थीं। आमतौर पर इस आयु वर्ग की महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त कर ली होती है और साथ ही उन्हें बच्चे भी हो गए होते हैं। महिलाओं के इस समूह ने अपने प्रसव वर्षों की शुरूआत भी ऐसे समय में की थी जब बड़े परिवार आदर्श थे, और परिणामस्वरूप, आज की युवा भारतीय महिलाओं को उनके जीवनकाल में होने वाले बच्चों की तुलना में इनके अधिक बच्चे हैं। वास्तव में, 40 से 49 की उम्र में महिलाओं के बच्चों की संख्या 1990 के दशक की प्रजनन दर के समान है: इस समूह में औसत भारतीय महिला को 3.2 बच्चे हुए, और धर्म के अनुसार अपेक्षाकृत ज़्यादा भिन्नताएँ हैं। ईसाई महिलाओं के परिवार सबसे छोटे होते हैं, जिनमें औसतन 2.6 बच्चे होते हैं, और मुसलमानों के सबसे अधिक बच्चे होते हैं - औसतन 4.2 बच्चे। हिंदू महिलाओं को औसतन 3.1 बच्चे हुए।

इस समूह में महिलाओं को भौगोलिक रूप से राज्यों और प्रदेशों में इस तरह से वितरित किया जाता है जो भारत की समग्र जनसंख्या को प्रतिबिंबित करता है। हिंदू या ईसाई महिलाओं की तुलना में 40 से 49 की उम्र की मुस्लिम महिलाओं की शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना अधिक होती है, और इस अंतर को ध्यान में रखते हुए, मुसलमानों के पास पारिवारिक संपत्ति कम होती है (ऐसे मापक के आधार पर जो कई कारकों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें क्या घरों में नलों में पानी आता है या क्या घरों में फर्श है शामिल हैं)। इस समूह में लगभग आधी महिलाओं ने बिल्कुल भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जिसमें 50% हिंदू, 57% मुस्लिम और 28% ईसाई शामिल हैं। इस समूह में महिलाओं के लिए शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या, हिंदुओं के लिए 4.2, मुसलमानों के लिए 3.2 और ईसाइयों के लिए 7.0 है।

विश्लेषण के परिणाम – शिक्षा के वर्षों के लिए नियंत्रित, पारिवारिक संपत्ति, महिलाओं का निवास राज्य, चाहे वे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में रहती हों और उनकी उम्र – दर्शाते हैं कि यदि 40 से 49 की उम्र में महिलाएँ इन सभी अन्य चीज़ों में समान हैं, तो औसतन, एक मुस्लिम महिला के 4.1 बच्चे (वास्तविक 4.2 से थोड़ा नीचे) होने के अनुमान की तुलना में , एक हिंदू महिला के 3.2 बच्चे (वास्तविक 3.1 से थोड़ा अधिक) होने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ।[8] दूसरे शब्दों में, यदि इस समूह की सभी महिलाओं के पास औसत धन और शिक्षा हो, उनकी उम्र एक समान हो और वे सभी एक ही क्षेत्र में रहती हों, तब भी औसतन, हिंदू महिलाओं को उनकी समकक्ष मुस्लिम महिलाओं की तुलना में 0.9 कम बच्चे होने का पूर्वानुमान लगाया जाता है।

[8] जबकि जाति एक मापी गई विशेषता है जो इस संदर्भ में प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है, यह इन अन्य कारकों से इतनी निकटता से जुड़ी हुई है कि इसे सांख्यिकीय मॉडल में शामिल नहीं किया जा सकता है।

दूसरी ओर, 40 से 49 की उम्र की एक औसत ईसाई महिला से 3.5 बच्चे होने की अपेक्षा की जाती है – इस आयु वर्ग की ईसाई महिलाओं के वास्तव में हुए बच्चों की संख्या से लगभग एक पूर्ण बच्चा ज़्यादा – यदि वह अन्य सभी भारतीय महिलाओं के समान है। ईसाइयों में वास्तविक बच्चों की संख्या और पूर्वानुमानित बच्चों की संख्या में इतना बड़ा अंतर मुख्य रूप से शिक्षा के स्तर में भिन्नताओं के कारण है। यदि ईसाई महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने की वर्षों की संख्या अधिक नहीं होती, तो उनके बच्चों की संख्या का हिंदुओं के काफी अधिक समान होने का पूर्वानुमान किया जाता।

जबकि ये कारक - शिक्षा के वर्ष, पारिवारिक संपत्ति, निवास स्थान और आयु - सभी सांख्यिकीय रूप से भारत में महिलाओं के बच्चों की संख्या से जुड़े हैं, वे धार्मिक समूहों के बीच प्रजनन अंतराल को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते हैं।

जैसा कि आमतौर पर कहीं अन्यत्र होता है, शिक्षा का प्रजनन क्षमता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष प्रजनन क्षमता मेंमहत्वपूर्ण गिरावट के साथ सहसंबंधित है। गरीब महिलाओं की तुलना में इस समूह की अमीर महिलाओं के कम बच्चे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के कम बच्चे हैं।

लेकिन ये परिणाम स्पष्ट करते हैं कि यदि इस समूह की सभी महिलाएँ शिक्षा और धन के स्तरों में बिल्कुल समान होती, एक ही क्षेत्र पर रह रही होती, और एक ही उम्र की होती, तब भी 40 से 49 की उम्र की हिंदू, मुस्लिम और ईसाई महिलाओं को होने वाले बच्चों की संख्या में अंतर होता। (मॉडलिंग और परिणामों पर अधिक विवरण के लिए कार्य-विधि देखें।)

वास्तव में, भारत में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई महिलाएँ कई मायनों में भिन्न हैं जो कि सर्वेक्षण डेटा के इस विश्लेषण में शामिल नहीं हैं और अक्सर इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है। ये परिणाम यह निर्धारित नहीं करते हैं कि प्रजनन क्षमता में अंतराल की कितनी मात्रा, यदि कोई हो, केवल धार्मिक संबद्धता के कारण है। वे केवल यह दिखाते हैं कि ऐसे कई अन्य कारकों को ध्यान में रखने के बावजूद, जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित और धार्मिक समूहों के बीच भिन्नता के लिए जाने जाते हैं, अंतर बने रहते हैं।

अन्य भिन्नताएँ नियंत्रित करने के बाद भी धर्म के अनुसार प्रजनन क्षमता में अंतर बना रहता है

एक औसत महिला के बच्चों की संख्या बनाम उस महिला से अपेक्षित बच्चों की संख्या, सांख्यिकीय नियंत्रणों के साथ

	वास्तविक संख्या	नियंत्रणों के साथ पूर्वानुमानित संख्या
हिंदू	3.1	3.2
मुस्लिम	4.2	4.1
ईसाई	2.6	3.5

ध्यान दें: धन, शिक्षा, आयु, शहरी/ग्रामीण सेटिंग और राज्य के लिए नियंत्रित किया गया हैं। मॉडलिंग और परिणाम पर विवरणों के लिए कार्य-विधि देखें।
स्रोत: 2015 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा का PEW रिसर्च सेंटर विश्लेषण
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर**

परिवर्तन के कारण: प्रवासन

हाल के वर्षों में कई लाखों लोग भारत छोड़ गए हैं या भारत आए हैं, लेकिन चूँकि उनकी संख्या समग्र जनसंख्या के सापेक्ष कम है, इसलिए प्रवासन का देश की धार्मिक संरचना पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है।

3:1 से अधिक के अनुपात में, भारत छोड़ने वाले लोगों की संख्या नवागंतुकों की संख्या से कहीं अधिक है। जब से संयुक्त राष्ट्र ने तीन दशक पहले इस तरह के आँकड़ों पर नज़र रखना शुरू किया है, तब से भारत अन्य देशों के अप्रवासियों के लिए मूल के शीर्ष देशों में से एक रहा है।[9] 2019 तक, भारत में पैदा हुए और दूसरे देशों में जाकर रहने वाले लगभग 175 लाख लोग थे। यह भारत की आबादी के एक छोटे-से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है: भारत में पैदा हुए केवल लगभग 1% लोग ही कहीं अन्यत्र रहते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय, जिनका वैश्विक आबादी में 17% से अधिक हिस्सा है, दुनिया के उन सभी लोगों का लगभग 6% हिस्सा है जो अपने जन्म के देश से बाहर रहते हैं।

भारत में पैदा हुए और अब विदेश में रहने वाले प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या संयुक्त अरब अमीरात (34 लाख), उसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका (27 लाख), सऊदी अरब (24 लाख), पाकिस्तान (16 लाख) और ओमान (13 लाख) में है। इन सभी देशों में, संयुक्त राज्य अमरीका को छोड़कर, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। भारत और फारस की खाड़ी के देशों के बीच आवाजाही अक्सर वृत्ताकार होती है, जिसमें प्रवासी समय-समय पर तेजी से विकसित हो रहे और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले अरब देशों में अस्थायी श्रमिकों के रूप में भारत छोड़कर जाते हैं।

प्रवासियों की धार्मिक संबद्धता पर 2012 की PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में संक्षेप में दिया गया जनगणना और सर्वेक्षण डेटा दर्शाता है कि भारत छोड़कर जाने वाले लोगों के बीच धार्मिक अल्पसंख्यकों अधिक प्रतिनिधित्व है। दुनिया भर में मुस्लिम प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत सबसे ऊपर है, जहाँ 30 लाख से अधिक भारत में जन्में मुसलमान अन्यत्र निवास कर रहे हैं – अनुमान से कहीं अधिक अन्यत्र जन्में और भारत में रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2019 में भारत में लगभग 52 लाख विदेश में जन्मे लोग रह रहे थे – जिनमें शरणार्थी, शरण चाहने वाले और अन्य अनियमित प्रवासी शामिल हैं – या उस वर्ष भारत की जनसंख्या का लगभग 0.4%। तुलनात्मक रूप से, संयुक्त राज्य अमरीका में 5,07 लाख से अधिक अप्रवासी थे, जो अमेरिकी आबादी का 15% हिस्सा थे।

भारत के अधिकांश अप्रवासी (31 लाख) बंगलादेश में पैदा हुए थे, जो कि बँटवारे तक भारत का हिस्सा था, और 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। अगले सबसे आम मूल पाकिस्तान (11 लाख), नेपाल (5,30,000), श्रीलंका (1,50,000) और चीन (1,10,000) हैं। बंगलादेश और पाकिस्तान, दोनों बड़े मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं; नेपाल मुख्य रूप से हिंदू देश है और श्रीलंका में बौद्ध बहुसंख्यक हैं। चीन की आबादी अधिकांशतः धार्मिक रूप से असंबद्ध है लेकिन जो क्षेत्र भारत के पड़ोसी हैं – तिब्बत और शिंजियांग – असामान्य है क्योंकि यहाँ क्रमश: बड़ी संख्या में बौद्ध और मुस्लिम हैं।

हालाँकि, कुछ प्रमाण यह संकेत करते हैं कि भारत में अप्रवासी जरूरी नहीं कि वे जिस देश से आए हैं, उसकी धार्मिक संरचना से मेल खाते हों। उदाहरण के लिए, PEW रिसर्च सेंटर के 2012 के अनुमानों के अनुसार, बंगलादेश से सभी अप्रवासियों में से 40% से अधिक हिंदू हैं, भले ही देश की 90% आबादी मुस्लिम है, जिनमें पाया गया कि कुल मिलाकर भारत के लगभग दो-तिहाई अप्रवासी हिंदू हैं। सबसे हाल के भारत मानव विकास सर्वेक्षण के अनुसार, उन

लोगों में, जिनके परिवार हाल की पीढ़ियों में भारत आए हैं, कुल मिलाकर, 87% हिंदू थे, 6% मुस्लिम, 6% सिख और लगभग 0.5% ईसाई थे।[9]

अवैध अप्रवास भारत में एक विवादास्पद विषय है और समय के साथ इसे सटीक रूप से मापना व्यावहारिक रूप से असंभव है, विशेष रूप से क्योंकि कानूनी या संरक्षित स्थिति के बारे में कानून पिछले वर्षों में बदल गए हैं। जबकि भारत शरणार्थियों को अपनाने के लिए तैयार रहा है, फिर भी उन्हें आमतौर पर कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही स्थितियाँ अनुमति दें, वे अपने गृह देश में लौट जाएँगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, मुस्लिम बहुल देशों में से लगभग करोड़ो लोग भारत में बिना किसी कानूनी दर्जे या दस्तावेज़ के निवास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बाह्यप्रवास और अन्य संकेतकों के लिए पर्याप्त सबूत के अभाव ने, इस तरह के उच्च अनुमानों की संभाव्यता के बारे में संदेह पैदा किया है। (संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य, जो कि प्रवासन डेटा पर निर्भर करती है, सभी अप्रवासियों को शामिल करता है, चाहे उनकी कानूनी स्थिति जो भी हो।)

[9] भारत मानव विकास सर्वेक्षण 40,000 से अधिक घरों का एक उच्च गुणवत्ता वाला, राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला पैनल सर्वेक्षण है।

साइडबार: भारत में प्रवासन और नागरिकता पर विवाद

पिछले दशक के दौरान नागरिकता और प्रवासन को लेकर भारत में तनाव बढ़ गए हैं। 2019 में, संसद ने कई हिंदू, ईसाई, जैन, सिख, पारसी और बौद्ध प्रवासियों को, - लेकिन मुस्लिम को नहीं - जो पड़ोसी देशों में उत्पीड़न से त्रस्त होकर भारत में शरण लेने आए हैं, शीघ्र नागरिकता प्रदान करने वाला नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया।

जो लोग भारत में या तो शरणार्थी के रूप में या बिना किसी दस्तावेज़ के आते हैं, अक्सर पपास के देशों के होते हैं, और अटकलें लगायी गई हैं कि हाल ही के वर्षों में लगभग करोड़ों मुस्लिम बंगलादेश और अन्य पड़ोसी देशों से भारत में अवैध रूप से रहने के लिए आ गए हैं।

इस तरह के उच्च अनुमानों के स्रोत और तरीके अस्पष्ट हैं, और बिना किसी दस्तावेज़ वाले लोगों का सही और विश्वसनीय अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन यदि पास के देशों से करोड़ों मुस्लिम सचमुच भारत में प्रवासित हुए हैं, तो जनसांख्यिकी विशेषज्ञ इस तरह के सामूहिक प्रवास का सबूत उनके मूल देश के डेटा में देखने की अपेक्षा करेंगे, और इस मात्रा में बाह्यप्रवास स्पष्ट नहीं है। इसके विपरीत, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग ने अनुमान लगाया कि 2019 तक, ऐसे 80 लाख से भी कम लोग थे जो बंगलादेश में पैदा हुए थे और अब *अन्य सभी देशों में रहते हैं* (कानूनी रूप से या अवैध रूप से)। माना जाता है कि बंगलादेश में पैदा हुए लगभग 31 लाख प्रवासी भारत में रहते हैं – यह भारत में आने वाले सभी अप्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन व्यापक रूप से उद्धृत किए गए, अक्सर बिना किसी सहायक प्रमाण के, कुछ आँकड़ों की तुलना में बहुत कम है।

उपलब्ध डेटा दर्शाता है कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की भारत छोड़कर जाने की संभावना अधिक है, और मुस्लिम बहुल देशों में से भारत आने वाले अप्रवासी अनुपातहीन रूप से हिंदू हैं। सांप्रदायिक संघर्ष से प्रेरित, बंगलादेश से भारत में हिंदुओं का बड़े-पैमाने पर प्रवासन, बंगलादेश की आबादी में हिंदुओं के हिस्से के लगातार कम होने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।(भारत में आने वाले और भारत से बाहर जाने वाले प्रवासियों की जनसांख्यिकी पर अधिक जानकारी के लिए, इस अध्याय में [10] "परिवर्तन के कारण: प्रवासन" देखें।)

बर्मा से मुख्य रूप से मुस्लिम रोहिंग्या लोगों के हालिया सामूहिक पलायन को भी भारत में अवैध प्रवास के स्रोत के रूप में उद्धृत किया गया है। जबकि यह संभव है कि कई रोहिंग्या भारत में हैं, फिर भी 2017-2018 में हुए सामूहिक पलायन से पहले केवल लगभग 10 लाख रोहिंग्या बरमा में रहते थे। बाद में, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि भारत में ऐसे लगभग 50,000 लोग रह रहे थे जो बरमा से थे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) में दर्ज लगभग 18,000 रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल थे। भारतीय अधिकारियों का अनुमान है कि पूरे देश में फैले हुए40,000 रोहिंग्या हैं।

[10] जनगणना के डेटा के अनुसार, ऐसे बंगलादेशियों का हिस्सा जो हिंदू हैं 1951 में 22.1% (जब बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तान था) से घटकर 2011 में 8.5% हो गया।

परिवर्तन के कारण: धार्मिक परिवर्तन

धर्म बदलने वाले भारतीयों का हिस्सा बहुत मामूली है और यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन का एक प्रमुख कारण प्रतीत नहीं होता है। जबकि भारत का संविधान नागरिकों को अपने धर्म का "अभ्यास, स्वीकार और प्रचार करने" की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वहीं ऐसे 9 भारतीय राज्य हैं जिनमें ऐसे कानून हैं जो लोगों को मुसलमान और ईसाई धर्म में धर्मांतरण का प्रयास करने और धर्मांतरण करने से प्रतिबंधित करते हैं। 1930 और 1940 के दशक में ब्रिटिश कब्जे के अंतिम दशकों के दौरान इस तरह के कानून पेश किए गए थे और 2000 के दशक में इनका प्रसार किया गया।

भारत भर में लगभग 30,000 वयस्कों के 2020 PEW रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में, बहुत कम लोगों ने बताया कि उन्होंने बचपन से अपना धर्म बदला है। उन वयस्कों में से, जो कहते हैं कि वे हिंदू के रूप में पले-बढ़े हैं, 99% अभी भी स्वयं की हिंदू के रूप में पहचान करते हैं। मुसलमानों के रूप में पले-बढ़े लोगों में से पूरे 97% वयस्कता में अभी भी मुसलमान हैं। और उन भारतीयों में से, जो ईसाई के रूप में पले-बढ़े हैं, 94% अभी भी ईसाई ही हैं। इसके अलावा, धर्म बदलने वाले लोगों की संख्या एक दूसरे को रद्द करती है; उदाहरण के लिए, सभी भारतीय वयस्स्कों में से, 0.7% हिंदू के रूप में पले-बढ़े थे, लेकिन अब वे उसी रूप में पहचान नहीं करते हैं, जबकि 0.8% धर्म से बाहर पले-बढ़े थे किन्तु अब हिंदू हैं।

अंतर्धार्मिक विवाह भी दुर्लभ है और इसका व्यापक रूप से विरोध किया जाता है। इसी सर्वेक्षण में, शादी शुदा हिंदुओं में से 99%, शादी शुदा मुसलमानों में से 98% और शादी शुदा ईसाइयों में से 95% लोगों का कहना है कि उनका/उनकी पति/पत्नी उन्हीं के धर्म का/की है। हिंदुओं और मुसलमानों के समान प्रतिशत और 92% ईसाइयों का कहना है कि उनका/उनकी पति/पत्नी उनके वर्तमान के धर्म में ही पला-बढ़ा/पली-बढ़ी है। इसके अलावा, 82% भारतीयों का कहना है कि उनके समुदाय की महिलाओं को दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने से रोकना कम से कम कुछ हद तक महत्वपूर्ण है, और 81% ने यही पुरुषों के लिए कहा, जिनमें लगभग दो-तिहाई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि प्रत्येक *अति* महत्वपूर्ण है। [ADD LINKS TO SURVEY REPORT IN THIS SECTION]

3. भारतीय राज्यों और प्रदेशों की धार्मिक जनसांख्यिकी

जैसा कि अधिकांश देशों में होता है, पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व व्यापक रूप से भिन्न है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश में, 2011 की जनगणना में करीब-करीब 20 करोड़ निवासी दर्ज किए गए थे, जबकि लक्षद्वीप के दक्षिणी द्वीपसमूह में 1,00,000 से भी कम थे। धार्मिक समूहों के अनुयायी भी पूरे देश में समान रूप से वितरित नहीं हैं।

परिणामस्वरूप, धार्मिक समूह विभिन्न प्रकार के स्थानीय संदर्भों में इस तरीके से रहते हैं जो ऊपर प्रस्तुत राष्ट्रीय पैटर्न में स्पष्ट नहीं हैं। कुछ मामलों में, एक निश्चित समूह के कई लाखों सदस्य एक बहुत बड़े राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। और अन्य मामलों में, अनुयायियों की बहुत छोटी सी संख्या भारत के एक छोटे से राज्यों में बहुसंख्यक का गठन करती है ।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के 35 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में से 28 राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक थे, जिनमें देश के सबसे अधिक आबादी वाले सभी राज्य शामिल थे: उत्तर प्रदेश (कुल आबादी 20 करोड़), महाराष्ट्र (11.2 करोड़), बिहार (10.4 करोड़) और पश्चिम बंगाल (9.1 करोड़).[11]

लक्षद्वीप के छोटे से उष्णकटिबंध द्वीपसमूह में (कुल आबादी 60,000) और जम्मू और कश्मीर (130 लाख) में, जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगकर है, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। बँटवारे के दौरान जम्मू और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग एक राज्य के रूप में उकेरा गया था, लेकिन 2019 में इसे अर्धस्वायत्त स्थिति से वंचित कर दिया गया और इसे सीधे भारत द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में लगभग 86 लाख मुस्लिम रहते थे, जो इसे सातवाँ सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला भारतीय राज्य बनाते थे।

नागालैण्ड (कुल आबादी 20 लाख), मिजोरम (10 लाख) और मेघालय (30 लाख) में ईसाई बहुसंख्यक हैं – भारत के उत्तर पूर्वीय भाग में, उपजाऊ पर्वत श्रृंखला में, कम आबादी वाले, तीन छोटे राज्य। केरल (3.3 करोड़) और तमिलनाडु (7.2 करोड़) जैसे अधिक बड़े राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में रहने वालों की तुलना में उनमें से किसी भी राज्य में कम संख्या में ईसाई रहते हैं ।

पंजाब में सिख सबसे बड़ा समूह है (कुल आबादी 2.8 करोड़), जो एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ हिंदुओं, मुसलमानों या ईसाइयों से इतर एक धार्मिक समूह एक बहुसंख्यक का निर्माण करता है। दो राज्यों, अरुणाचल प्रदेश (1.4 करोड़) और मणिपुर (30 लाख) की आबादियाँ धार्मिक रूप से विविध हैं, जिसमें कई धार्मिक समूहों के पर्याप्त हिस्से हैं और कोई भी बहुसंख्यक नहीं है।

[11] जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह रिपोर्ट 2011 की जनगणना के समय भारत के भूगोल पर आधारित है। तब से, एक नए राज्य का निर्माण हुआ है: तेलंगाना (जिसकी राजधानी हैदराबाद है) का निर्माण 2014 में आंध्रप्रदेश के एक हिस्से से हुआ था। जम्मू और कश्मीर, जो कि एक राज्य था, 2019 में दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया: जम्मू और कश्मीर, तथा लद्दाख। 2020 में, दादरा और नगर हवेली का दमन और दीव के साथ विलय हो गया। परिणामस्वरूप, 2021 में भारत में कुल 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश थे।

अधिकांश भारतीय राज्यों में हिंदू धर्म सबसे बड़ा समूह है।

सबसे बड़ा धार्मिक समूह और राज्य और प्रदेश के अनुसार उसका हिस्सा

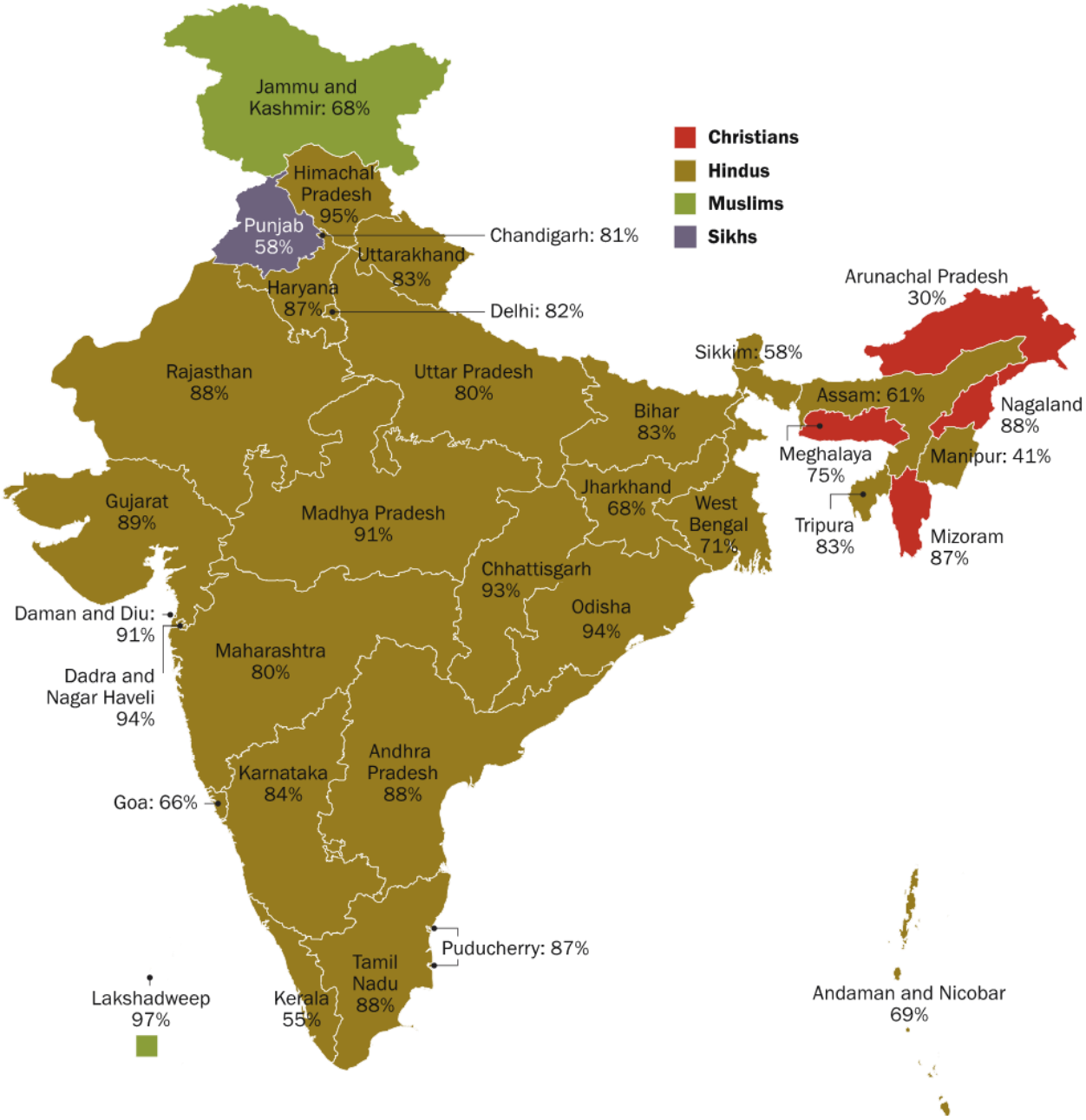

ध्यान दें: तेलंगाना (नहीं दिखाया गया है) का निर्माण आंध्र प्रदेश के एक हिस्से से हुआ है। जम्मू और कश्मीर को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, और दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के साथ विलय हो गया है।
स्रोत: भारत की जनगणना, 2011।
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर**

यद्यपि इस अध्याय में चर्चा की गई जनसंख्या हिस्सेदारी 2011 में हुई पिछली भारतीय जनगणना के अनुसार है, लेकिन राज्य में बहुसंख्यक आमतौर पर इतने बड़े हैं कि उन्हें एक दशक में 50% से नीचे जाने की उम्मीद नहीं होगी।

यदि कुल संख्या की बात की जाए, तो हिंदुओं (15.9 करोड़, या सभी भारतीय हिंदुओं का 16%) और मुसलमानों (3.8 करोड़, या मुसलमानों का 22%) दोनों की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, जबकि ईसाइयों की सबसे बड़ी संख्या (0.6 करोड़, या ईसाइयों का 22%) केरल में रहती है। अधिकांश सिख पंजाब में रहते हैं (1.6 करोड़, या भारतीय सिखों का 77%)।

बौद्ध अक्सर भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं (65 लाख, या भारतीय बौद्धों का 77%)। महाराष्ट्र, भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य – जिसमें मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर शामिल है – भी ऐसा राज्य है जिसमें जैनों की सबसे बड़ी संख्या है (14 लाख, या जैनों का 31%)।

भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों और प्रदेशों में बड़ी संख्या में हिंदू बहुसंख्यक हैं, जबकि कुछ छोटे राज्यों में मुस्लिम और ईसाई बहुसंख्यक हैं।

राज्य और प्रदेश के अनुसार प्रत्येक धार्मिक समूह का %

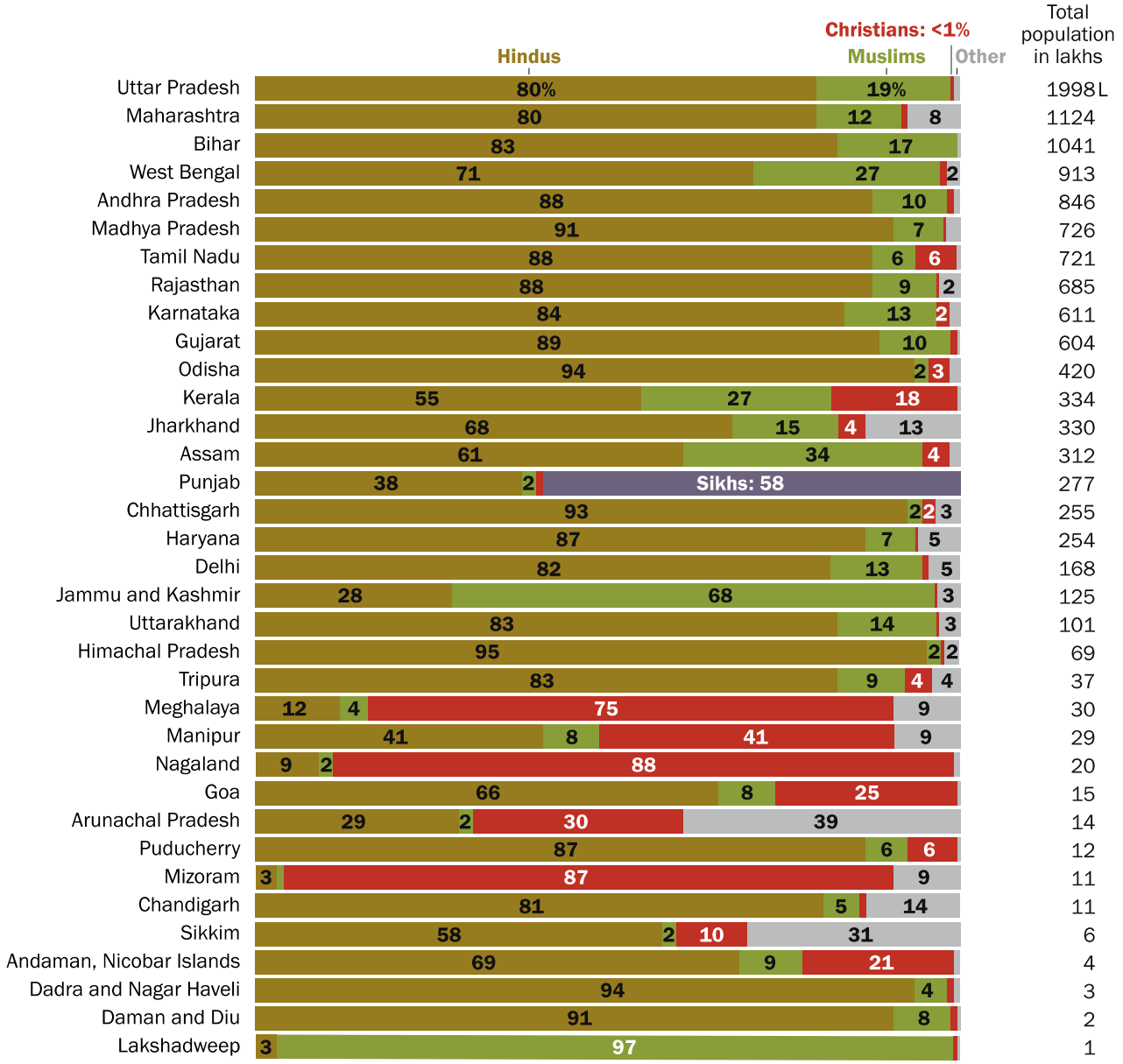

ध्यान दें: सिखों को केवल पंजाब में अलग से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वे वहाँ 58% के साथ बहुसंख्यक हैं। तेलंगाना (नहीं दिखाया गया है) का निर्माण आंध्र प्रदेश के एक हिस्से से हुआ है। जम्मू और कश्मीर को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, और दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के साथ विलय हो गया है।
स्रोत: भारत की जनगणना, 2011।
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर**

राज्य स्तर पर, हाल के जनगणना दशक में धार्मिक विभाजन अपेक्षाकृत स्थिर थे।

जबकि इस रिपोर्ट में से अधिकांशतः 1951 की स्वतंत्रता-पश्चात् की पहली जनगणना के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक संरचना में हुए बदलाव का अध्ययन किया गया है, किन्तु इस अनुभाग में 2001 और 2011 की जनगणना के बीच की अवधि में राज्यों के भीतर हुए विकासों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

उस दशक के दौरान अपने 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भारत की आंतरिक सीमाएँ काफी हद तक स्थिर थीं, जिससे धार्मिक समूहों के सापेक्षिक आकारों में राज्य स्तर पर हुए बदलावों को ट्रैक करना संभव था। 2001 के पहले, राज्यों और प्रदेशों की सीमाएँ काफी बार बदली, जिससे एक जनगणना से दूसरी जनगणना की तुलना करना मुश्किल था। (भारत के बदलते भूगोल पर अधिक जानकारी के लिए साइडबार देखें।)

कुल मिलाकर, 2001 और 2011 के बीच राज्यों की धार्मिक संरचना में अपेक्षाकृत कम बदलाव आया, विशेष रूप से अधिक घनी आबादी वाले राज्यों में, जब कि लगभग हर राज्य की आबादी में बहुत वृद्धि हुई। राज्यों के भीतर, धार्मिक समूहों की हिस्सेदारी शायद ही कभी 3 प्रतिशत अंक से अधिक बढ़ी या गिरी, और ज्यादातर मामलों में, वे 1% के एक छोटे से अंश से अधिक नहीं बदले।

यह ख़ासकर हिंदुओं के लिए सही था, जिनकी संख्या आम तौर पर 2001 और 2011 के बीच राज्य की आबादी के हिस्से के रूप में स्थिर रही या इसमें मामूली गिरावट देखी गई। उदाहरण के लिए, इस दशक के दौरान उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की हिस्सेदारी 0.9 प्रतिशत अंक गिरी है, और महाराष्ट्र में हिंदुओं का प्रतिशत 0.5 अंक गिरा कम हुआ। इस प्रवृत्ति का एक अपवाद पंजाब था, जहाँ हिंदुओं की हिस्सेदारी में 1.6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई।

भारत के ज्यादातर राज्यों में, आबादी की हिस्सेदारी के रूप में हिंदुओं की संख्या स्थिर रही है या इसमें थोड़ी गिरावट रही है।

राज्य के अनुसार हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में प्रतिशत अंक परिवर्तन, 2001-2011

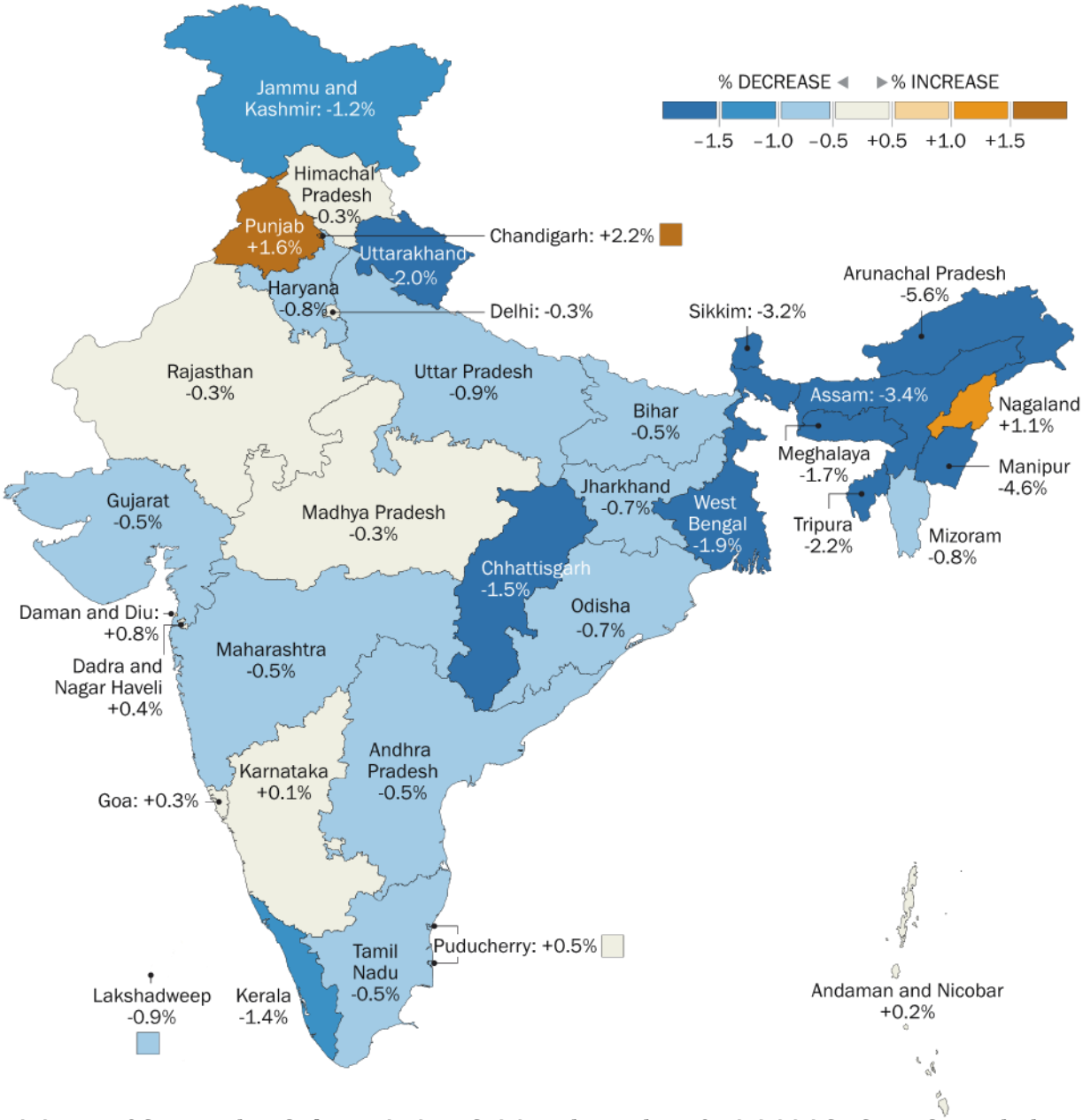

ध्यान दें: तेलंगाना (नहीं दिखाया गया है) का निर्माण आंध्र प्रदेश के एक हिस्से से हुआ है। जम्मू और कश्मीर को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, और दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के साथ विलय हो गया है।
स्रोत: PEW रिसर्च सेंटर द्वारा 2001-2011 भारतीय जनगणना डेटा का PEW रिसर्च सेंटर विश्लेषण
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर**

2001 और 2011 के बीच मुसलमानों ने आमतौर पर राज्यों के भीतर अपनी आबादी की हिस्सेदारी बनाए रखी या उन्हें थोड़ा सा बढ़ाया। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल की आबादी के हिस्से के रूप में मुसलमा 1.8 प्रतिशत बढ़े, और जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक 1.3 अंक बढ़े। एकमात्र राज्य जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी में गिरावट हुई, वह था मणिपुर, जिसमें 0.4 अंकों की गिरावट हुई।

भारत के ज्यादातर राज्यों में आबादी के हिस्से के रूप में मुसलमानों की संख्या थोड़ी बढ़ी है।

राज्य अनुसार मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में प्रतिशत अंक परिवर्तन, 2001-2011

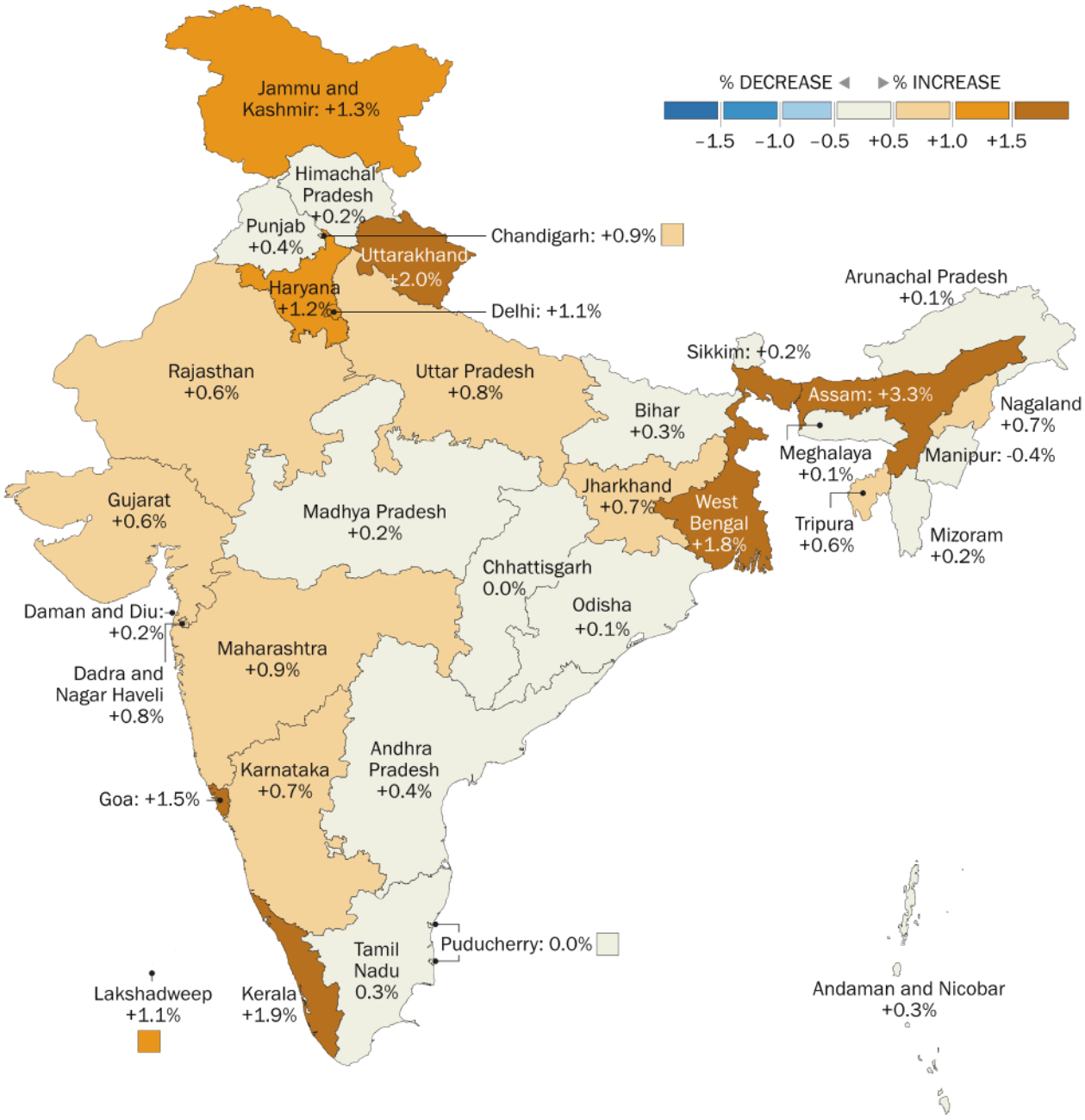

ध्यान दें: तेलंगाना (नहीं दिखाया गया है) का निर्माण आंध्र प्रदेश के एक हिस्से से हुआ है। जम्मू और कश्मीर को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, और दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के साथ विलय हो गया है।
स्रोत: 2001-2011 भारतीय जनगणना डेटा का PEW रिसर्च सेंटर विश्लेषण
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW **रिसर्च सेंटर**

धार्मिक समूहों की आबादी की हिस्सेदारियों में कुछ सबसे प्रभावशाली परिवर्तन भारत के अलग-थलग पूर्वोत्तर में थे।

केवल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ईसाइयों की आबादी की हिस्सेदारी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। असम के अपवाद साथ (आबादी 3.1 करोड़), पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत कम आबादी है – सिक्किम में 6,10,000 से लेकर त्रिपुरा में 37 लाख तक – इसलिए धार्मिक समूहों की संख्या में मामूली उतार-चढ़ाव भी उनके सापेक्ष आकार को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में, इस पहाड़ी क्षेत्र में समग्र धार्मिक संरचना में परिवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट थे, जो कि चीन, बंगलादेश, बरमा, भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हैऔर भारत के बाकी हिस्से से काफी अलग-थलग है।

ईसाई में, जो की राष्ट्रीय आबादी के प्रतिशत की तुलना में इस क्षेत्र में आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, 2001 और 2011 के बीच कई राज्यों के प्रतिशत के रूप वृद्धि हुई। ईसाइयों की हिस्सेदारी, अरुणाचल प्रदेश में 12% अंकों से (30% हो गई), मणिपुर में 7 अंकों से (41% हो गई), मेघालय में 4 अंकों से (75% हो गई) और सिक्किम में 3 अंकों से (10% हो गई) बढ़ी। नागालैंड में ईसाइयों की हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई, यद्यपि वे भारी बहुमत में बने रहे।

हिंदुओं के भी प्रतिशत अंक में सबसे बड़े बदलाव कम आबादी वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे; कुल मिलाकर 3 या अधिक अंकों की गिरावट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में (6 प्रतिशत अंक गिरकर 29%), मणिपुर (-5 अंक गिरकर 41%), असम (-3 अंक गिरकर 61%) और सिक्किम (-3 अंक गिरकर 58%)। मुसलमानों ने भी सबसे बड़ा परिवर्तन पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुभव किया असम में (+3 अंक से बढ़कर 34%)।

भारत के कम आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई आबादी के हिस्से बढ़े हैं

राज्य अनुसार ईसाई आबादी की हिस्सेदारी में प्रतिशतअंक परिवर्तन, 2001-2011

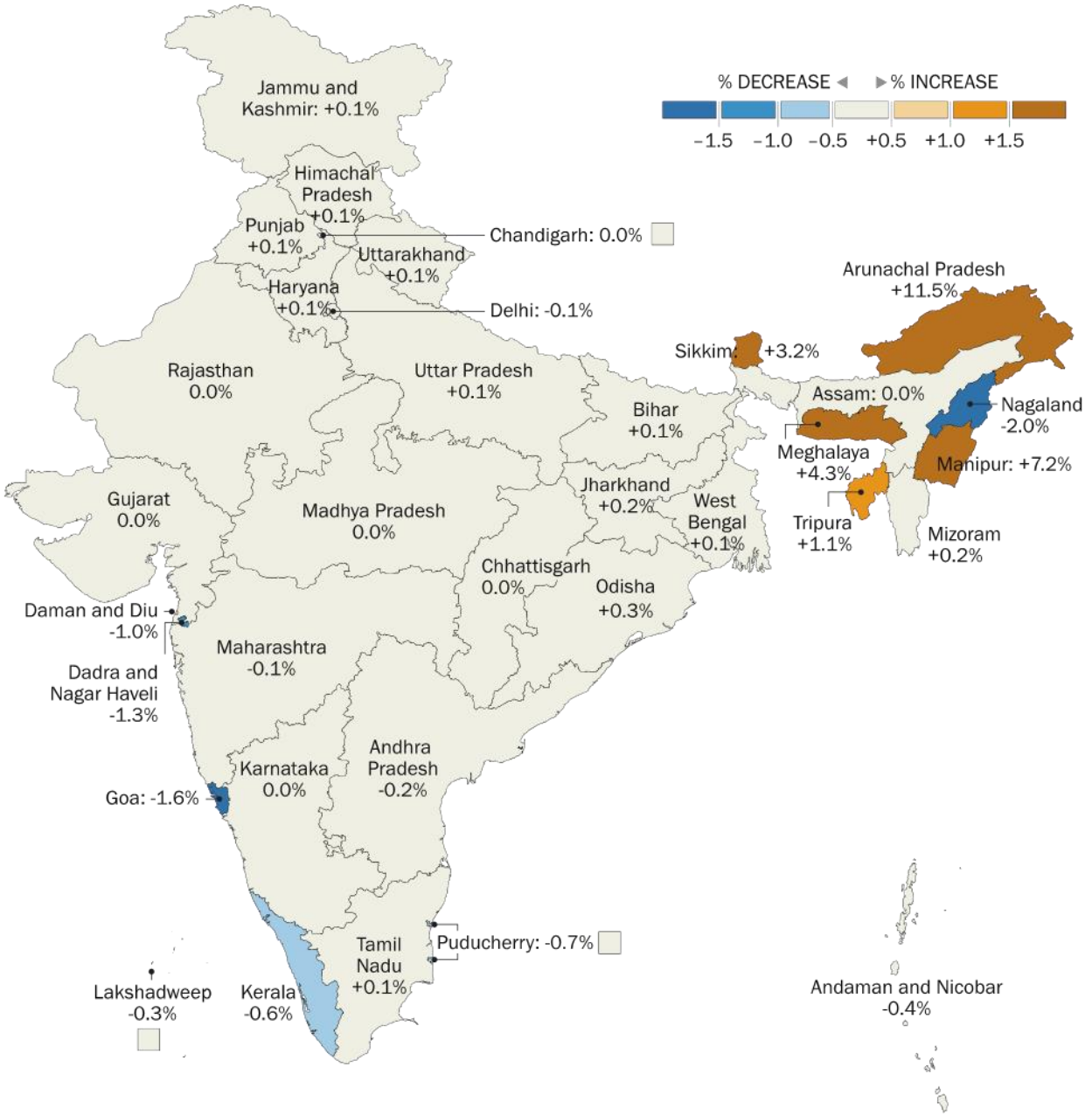

ध्यान दें: तेलंगाना (नहीं दिखाया गया है) का निर्माण आंध्र प्रदेश के एक हिस्से से हुआ है। जम्मू और कश्मीर को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, और दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली का विलय हो गया है।
स्रोत: 2001-2011 भारतीय जनगणना डेटा का PEW रिसर्च सेंटर विश्लेषण
"भारत की धार्मिक संरचना"

PEW रिसर्च सेंटर

कुछ बड़े राज्यों ने अपने धार्मिक परिदृश्यों में पर्याप्त परिवर्तनों का अनुभव किया है

असम के अलावा, कम से कम 1 करोड़ की आबादी वाले केवल चार अन्य राज्यों में कोई धार्मिक समूह थे जिन्होंने, 2001 और 2011 के बीच राज्य की आबादी की अपनी हिस्सेदारी में 2 प्रतिशत अंक या उससे अधिक के परिवर्तनों का अनुभव किया।

- पश्चिम बंगाल (आबादी 9.1 करोड़) में, हिंदुओं का प्रतिशत 2 प्रतिशत अंक गिरकर 71% हो गया और मुसलमान 2 प्रतिशत अंक बढ़कर 27% हो गए।
- पंजाब में (2.8 करोड़), सिख बहुसंख्यक 2 अंक घटकर 58% हो गए।
- केरल में (3.3 करोड़), मुसलमानों की हिस्सेदारी 2 अंक बढ़कर 27% हो गई।
- और उत्तराखण्ड (1 करोड़) में, हिंदुओं की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत अंक घट कर 83% हो गई, जबकि मुसलमानों की हिस्सेदारी 2 अंक बढ़कर 14% हो गई।

भारत के तीनों सबसे बड़े धार्मिक समूहों की कुल संख्या लगभग हर राज्य में बढ़ी।

निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में, लगभग हर भारतीय राज्य में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई बढ़े। केवल एक राज्य, ईसाई बहुल मिजोरम में, हिंदुओं की संख्या में थोड़ी गिरावट (लगभग 1,500 की) हुई, जबकि ईसाइयों की संख्या, नागालैण्ड और आंध्रप्रदेश दोनों में लगभग 50,000 कम हुई। इस दशक के दौरान किसी भी राज्य में मुसलमानों की कुल संख्या में कोई खास गिरावट नहीं हुई।

संख्या के अनुसार, हिंदुओं ने अपनी सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि का अनुभव, भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश में किया, जो कि 2.5 बढ़ी (15.9 करोड़ हो गई), उसके बाद बिहार में, जहाँ हिंदुओं की आबादी 1.7 करोड़ बढ़ी (8.6 करोड़ हो गई)। उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों में गरीबी औसत दरों से अधिक है और, संबंधित रूप से, असाधारण रूप से उच्च प्रजनन दर है।

मुस्लिम आबादी की भी सबसे अधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई, 80 लाख बढ़ी (3.8 करोड़ हो गई), उसके बाद पश्चिम बंगाल 40 लाख तक बढ़ी (2.5 करोड़ हो गई)। पश्चिम बंगाल में गरीबी और प्रजनन दर औसत दर से थोड़े कम हैं।

ईसाइयों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि तमिलनाडु में हुई, जहाँ यह आबादी 6,00,000 बढ़ी (40 लाख हो गई) और मेघालय में भी 6,00,000 बढ़ी (22 लाख हो गई)। जबकि सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में प्रजनन दर कम है, जबकि पूर्वोत्तर में मेघालय में प्रजनन दर अधिक है।

कार्य-विधि

इस अनुभाग में इस रिपोर्ट में विश्लेषण के लिए उपयोग किए गए स्रोतों और चरों का वर्णन किया गया है। यह डेटा की ज्ञात सीमाओं की व्याख्या करता है। इसके बाद, यह उपयोग किए गए मानचित्र की ताक़तों, कमजोरियों और विकल्पों को, और साथ ही कुछ क्षेत्रों में डेटा क्यों उपलब्ध नहीं है, इसके कारणों को दर्शाता है। अंत में, अध्याय 2 के अनुभाग "परिवर्तन के कारण: प्रजनन" में उपयोग किए गए बहुस्तरीय मिश्रित-प्रभाव मॉडलिंग का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है।

स्रोत

इस रिपोर्ट में मात्रात्मक विश्लेषण दो मुख्य स्रोतों पर भरोसा करते हैं: भारत की दशवार्षिक जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)। 1951 से 2011 तक की जनसंख्या के आकारों की जानकारी जनगणना से आए है। जनगणना ने 1881 से, जब भारत अभी भी अंग्रेजों के शासन के अधीन था, धर्म सहित, व्यक्तियों और परिवारों पर विस्तृत डेटा एकत्रित किया है।

प्रजनन क्षमता पर डेटा और यह महिला के राज्य, उसकी आयु, शिक्षा के वर्ष, पारिवारिक संपत्ति और शहरी बनाम ग्रामीण स्थिति से कैसे संबंधित है, इसका डेटा भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से आया है। NFHS एक बड़ा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण है जिसमें जनगणना की तुलना में बच्चे के जन्म पर अधिक व्यापक जानकारी है। पहला दौर 1992-93 में आयोजित किया गया था। इसके उपलब्ध चार दौरों में से प्रत्येक की कुल प्रजनन दर शामिल की गई है। इस बात का विश्लेषण कि विभिन्न कारक 40 से 49 की उम्र की महिलाओं को होने वाले बच्चों की संख्यासे कैसे संबंधित हैं, केवल 2015 और 2016 में आयोजित किए गए सर्वेक्षण के चौथे दौरे पर निर्भर करता है। प्रकाशन के दिन तक, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) का पाँचवा दौर प्रगति पर है। जनसंख्या की हर एक इकाई पर डेटा (माइक्रोडेटा) बाद में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे धर्म के आधार पर प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना संभव होगा। उन राज्यों के लिए कुल प्रजनन दर (टीएफआर) के प्रारंभिक परिणाम जारी किए गए हैं जिनमें डेटा संग्रह पहले ही पूरा हो चुका है: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1680702.

समस्त भारतीय महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता के ऐतिहासिक पैटर्न के संक्षिप्त संदर्भ संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना से आए हैं। भारत में जन्मे लोगों के प्रवासन का डेटा भी संयुक्त राष्ट्र से आता है और इस डेटा के आधार पर Pew रिसर्च सेंटर उन लोगों की धार्मिक संरचना का विश्लेषण करता है। भारतीय राज्यों के विकास के स्तरों की तुलनाएँ मानव विकास सूचकांक के स्कोर पर आधारित हैं - जो कि एक समग्र मापक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, स्कूलिंग के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति आय जैसे आयाम शामिल हैं।

धार्मिक परिवर्तन और अंतर्धार्मिक विवाहों पर सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएँ, 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में आयोजित 29,999 भारतीय वयस्कों के Pew रिसर्च सेंटर सर्वेक्षण से आयी हैं। भविष्य की जनसंख्या के आकार के अनुमान भी सेंटर द्वारा लगाए गए थे।

डेटा की सीमाएँ

भारत में धर्म पर जनगणना के डेटा के साथ ज्ञात समस्याएँ हैं। ईसाई विशेष रूप से कम गिने जाते प्रतीत होते हैं; कुछ ईसाई जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, जनगणना जैसे आधिकारिक प्रपत्रों को पूरा करते समय हिंदू के रूप में पहचान करना चुन सकते हैं। यह भारतीय संविधान में एक जनादेश के कारण है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग ही कुछ जाति-आधारित सरकारी सकारात्मक योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकते हैं (भारत में इसे आरक्षण के नाम से जाना जाता है)। Pew रिसर्च सेंटर की वैश्विक धार्मिक परिदृश्य और विश्व धर्मों का भविष्य रिपोर्ट्स के विश्लेषण में दर्शाया गया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में 10% ईसाई जनगणना में अपनी सम्बद्धता हिंदू के रूप में कहते हैं और तदनुसार समायोजित किए गए हैं। छह दशकों में प्रतिक्रियाओं में पूर्वाग्रह में होने वाले बदलाव को लेकर अनिश्चितता होने के कारण, यह रिपोर्ट असमायोजित संख्याओं पर भरोसा करती है।

बौद्धों, जैनियों और सिखों को कुछ ऐसे कानूनों में हिंदुओं के साथ समूहित किया जाता है जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के लिए जन सेवाओं या रोजगार और शैक्षिक प्राथमिकताओं तक पहुँच को सक्षम बनाते हैं। हो सकता है कि जनगणना करने वालों और प्रगणकों के बीच इस बात को लेकर कुछ भ्रम हो कि कौन सी धार्मिक संबद्धताएँ किन परिस्थितियों और सरकारी प्रपत्रों पर लागू होती हैं।

2010 में दिल्ली में हुई एशियाई जनसंख्या संघ की बैठक में अग्रणी भारतीय जनसांख्यिकी विशेषज्ञों के साथ भारतीय जनगणना में धर्म पर हुए एक परामर्श के दौरान पेश किए गए उपाख्यान में यह बताया गया कि कैसे, उत्तरदाताओं से उनकी धार्मिक संबद्धता के बारे में पूछने के बजाय, कुछ जनगणना प्रगणकों ने व्यक्तियों के नाम या उनके घरों में रखी चीज़ों या प्रतीकों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। दूसरों ने किसी धार्मिक या सामुदायिक नेता से आस-पास के व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में पूछा होगा। ये प्रथाएँ जनगणना प्रोटोकॉल के साथ असंगत हैं और इनमें बहुसंख्यक धर्म, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रही प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं, लेकिन इस विषय पर कोई ज्ञात मात्रात्मक डेटा नहीं है।

जबकि, संवैधानिक रूप से, भारत धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा के साथ एक धर्मनिरपेक्ष देश है, Pew रिसर्च सेंटर के एक वार्षिक अध्ययन के अनुसार आम तौर पर भारतीय अभी भी धर्म पर सरकारी प्रतिबंधों के "उच्च" स्तर का अनुभव करते हैं। ऐसे नौ राज्य हैं जिनमें ईसाइयों और मुसलमानों के लिए धर्मांतरण का प्रयास करना अवैध है। धर्म पर सरकारी प्रतिबंध जनगणना करने वालों को, वे जिस धर्म का पालन करते हैं या जिसमें विश्वास करते हैं, उससे इतर कोई अन्य धार्मिक संबद्धता लिखने के लिए प्रभावित कर सकते हैं, यद्यपि Pew रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में भी यह भी पाया गया है कि धार्मिक परिवर्तन असामान्य है।

मानचित्र सीमाएं और अनुपलब्ध डेटा

इस रिपोर्ट में सारे में उपयोग किया गया मानचित्र टेम्प्लेट भारत की जनगणना के मानचित्र पर आधारित है। यह भारत के कई मानचित्रों में से एक है, और इसकी ताक़तें और कमजोरियाँ, दोनों हैं। यहाँ उपयोग किया गया मानचित्र भारत सरकार के अनुसार निर्धारित की गई राज्यों और प्रदेशों की सीमाओं को दर्शाता है, जिसमें उनके भीतर के क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनके लिए 2011 में डेटा उपलब्ध नहीं था। डेटा अनुपलब्ध होने के कारण अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात के पश्चिमी राज्य का एक हिस्सा वर्षा-ऋतु में आमतौर पर जमा हुए पानी में डूबा हुआ होता है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप, आधिकारिक तौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक क्षेत्र का हिस्सा, सेंटिनलीज का घर है, जो कि एक ऐसी जनजाति है जिससे कोई संपर्क नहीं होता है। जनजाति का बाहरी लोगों के विरुद्ध जोरदार

हमला करने का लंबा इतिहास है, जिसमें द्वीप पर आनेवाली नौकाओं पर हमले करना शामिल हैं जिससे संभावित आगंतुकों की हत्या हुई है। द्वीप की भारत सरकार द्वारा दूर से सुरक्षा की जाती है और इस पर निगरानी रखी जाती है लेकिन यह प्रभावी रूप से संप्रभु है।

जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है, पाकिस्तान द्वारा कब्जा किये गए कश्मीर के क्षेत्र को कवर करता है, जहाँ भारतीयों का जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। राज्य के उत्तरपूर्वी हिस्से पर 1950 के दशक से चीनी सेना का कब्जा है, लेकिन यह ज़्यादातर निर्जन है। जबकि भारत सरकार जम्मू और कश्मीर कहे जाने वाले पूरे क्षेत्र को स्पष्ट रूप से भारत का हिस्सा मानती है और लंबे समय से चले आ रहे कब्जों को अवैध मानती है, किन्तु पाकिस्तान और चीन की सरकारें ऐसा नहीं मानती हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन क्षेत्रों को विवादित मानते हैं। इस क्षेत्र पर किन देशों के दावे वैध हैं, इस बात पर Pew रिसर्च सेंटर कोई रुख नहीं अपनाता है। बल्कि, यह मानचित्र इसलिए चुना गया क्योंकि यह मुख्य डेटा स्रोत के संगत है और आमतौर पर भारत के लोगों द्वारा इसे सटीक के रूप में स्वीकार किया जाता है।

मॉडलिंग पर विस्तृत जानकारी

यह अनुमान लगाने के लिए कि धार्मिक समूहों के बीच अन्य अंतरों द्वारा प्रजनन क्षमता की भिन्नताओं को किस हद तक समझाया जा सकता है, धर्म, प्रजनन क्षमता और इसके सहसंबंधों के बीच संबंधों पर इस रिपोर्ट का यह अनुभाग उन बच्चों की पूर्वानुमानित संख्या प्रस्तुत करता है जो एक औसत भारतीय महिला के 40 से 49 की उम्र में हो सकते हैं। अन्य कारकों के लिए नियंत्रण करते हुए इनकी गणना, एक गाउसियन वितरण मानकर, एक भारित बहुस्तरीय मिश्रित-प्रभाव सामान्यीकृत रैखिक मॉडल का उपयोग करके की गई थी। नमूने में एनएफएचएस (सबसे हाल के जिसके लिए माइक्रोडेटा उपलब्ध है) की चौथी लहर में 40 से 49 वर्ष की आयु की 1,49,294 ऐसी महिलाएँ शामिल हैं जिनकी कभी न कभी शादी हुई है। इस मॉडल के लिए धार्मिक संबद्धता, शहरी बनाम ग्रामीण सेटिंग और कारकों के रूप में दो के बीच के परस्पर क्रिया को ध्यान में रखा गया है। इसमें सामान्य पारिवारिक संपत्ति स्कोर, स्कूलिंग के वर्षों और उम्र के रैखिक और अरैखिक प्रभाव भी ध्यान में रखे गए हैं। ऐसी महिलाओं को नमूने के रूप में लिया गया जो ज़िलों में निवास कर रही हैं (एनएफएचएस में प्राथमिक नमूनाकरण इकाई), जिसमें राज्यों के भीतर ये ज़िले शामिल थे। मॉडल में एक रैंडम स्लोप शामिल है जो धर्म के प्रभाव को एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होने की अनुमति देता है।

ये समूह पहली शादी और पहले जन्म के समय अपनी औसत आयु में भी भिन्न होते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में 40 से 49 की महिलाओं ने, औसतन, 18 साल की उम्र में पहली बार शादी की, और ईसाइयों में औसत आयु 21 थी। औसतन, हिंदू महिलाओं ने अपने पहले बच्चे को 21 वर्ष की आयु पर जन्म दिया, मुसलमानों ने 20 वर्ष पर और ईसाइयों ने 22 वर्ष पर। चूँकि ये कारक प्रजनन क्षमता से भी संबंधित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें मॉडल की मजबूती की जाँचों में शामिल किया गया था। आम तौर पर परिणाम इन अतिरिक्त चरों के साथ या बिना स्थिर होते हैं। ईसाइयों को होने वाले बच्चों की पूर्वानुमानित संख्या 3.8 है यदि पहली शादी और जन्म के समय की आयु को ध्यान में लिया जाए, और यदि इन्हें ध्यान में न लिया जाए तो वही संख्या 3.5 है। जब इन चरों को शामिल किया जाता है तो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पूर्वानुमानों में 0.1 से कम परिवर्तन होते हैं। क्योंकि प्रथम विवाह और जन्म के समय आयु का शिक्षा से निकटता से संबंध है, और इन्हें बाहर करने से परिणाम सार्थकरूप से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए ओवरफिटिंग से बचने के लिए, इन्हें अंतिम मॉडल में से हटा दिया गया था।